सुविचार
शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा।
-कैफी आजमी

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Tuesday, 20 January 2026 ● Year : 05 ● Issue : 08 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12
Nora Fatehi Reacts To Alleged...

SHARE

सेंसेक्स	:	83,246.18
निफ्टी	:	25,585.50

SARAFA

सोना	:	13,555
चांदी	:	318.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

दो वाहनों की टक्कर में चार की मौत, 20 घायल

MUMBAI : सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव-मनमाड हाइवे पर वराडे गांव के पास एक निजी बस और एक पिकअप के बीच हुई जोरदार टक्कर में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। इन सभी को मालेगांव उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की छानबीन मालेगांव पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। जांच पुलिस अधिकारी ने बताया कि निजी बस पुणे से मालेगांव की ओर जा रही थी। निजी बस जैसे ही वराड़े गांव के पास पहुंची अचानक सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गई। इस घटना में चार लोगों को मौत हो गई और २० लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पर मालेगांव पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मालेगांव उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।

अमेरिकी धमकी के बाद 7 देशों के सैनिक पहुंचे ग्रीनलैंड

NEW DELHI : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके लिए यूरोपीय देशों में फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं, जो 27वीं माउंटेन इन्फैंट्री ब्रिगेड से हैं। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने दो-दो सैनिक तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने एक सैन्य अधिकारी भेजा है। स्वीडन ने भी सैनिक भेजने की पुष्टि की है, हालांकि संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। कुल मिलाकर, डेनमार्क के मौजूदा सैनिकों के अलावा यूरोपीय देशों से लगभग 35-40 सैन्य कर्मी पहुंचे हैं। वहीं, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेत्तो ने इस पूरे ऑपरेशन को मजाक जैसा बताया है।

नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं : ट्रंप

NEW DELHI : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नोबेल न मिलने की शिकायत की गई है। पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला। इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे लिखा- शांति जरूरी है, लेकिन अब वह यह भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी कोशिश की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना भी है। इसकी वजह से उनके फैसले पर भी असर पड़ रहा है। नॉर्वे के पीएम ने ट्रंप की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। दरअसल, उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मिलकर ट्रंप को टैरिफ बढ़ाने के फैसले के विरोध में एक चिट्ठी भेजी थी। इसके जवाब में ट्रम्प ने नोबेल न मिलने की शिकायत कर दी।

हाईकोर्ट ने दिया कड़ा आदेश : मिट्टी निकालने का मामला, मालिकों की याचिका खारिज

ईंट भट्ठा संचालकों को पर्यावरण स्वीकृति और सीटीओ की अनुमति लेना अनिवार्य

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में आदेश दिया कि ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालने पर अब ईंट भट्ठा संचालकों को पर्यावरण स्वीकृति (पर्यावरण मंजूरी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीटीओ) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) में भी कमाई का एक हिस्सा जमा करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने ईंट भट्ठा मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी लघु खनिज (माइनर मिनरल) की श्रेणी में आती है, इसलिए इस पर झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2004 पूरी तरह लागू होंगे। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के ईंट भट्ठा संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि मिट्टी निकालने के लिए पर्यावरण स्वीकृति और सीटीओ की जरूरत नहीं है।

- जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में हुई सुनवाई
- झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2004 पूरी तरह होंगे लागू
- पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के ईंट भट्ठा संचालकों ने दाखिल की थी रिट

कमाई का एक हिस्सा डीएमएफटी को भी करना होगा भुगतान, लघु खनिज मिनरल की श्रेणी में आती है मिट्टी

भूमि, जल और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव

ईंट भट्ठे खनन की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए डीएमएफटी का भुगतान नहीं लिया जा सकता है। ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईंट निर्माण की प्रक्रिया मिट्टी निकालने से शुरू होती है, इसलिए मिट्टी का उत्खनन और ईंट निर्माण को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। मिट्टी भी पर्यावरण का हिस्सा है, बड़े पैमाने पर इसका उत्खनन करने से भूमि, जल और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार की कार्रवाई को कोर्ट ने ठहराया उचित

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पहले ही ईंट बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी को माइनर मिनरल घोषित कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि खनिज संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर असर पड़ता है। इसी की भरपाई के लिए ही डीएमएफटी फंड बनाया गया है, इसलिए ईंट भट्ठा संचालकों को भी इस फंड में योगदान देना होगा। इन सभी आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिका को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया और राज्य सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया।

खनन पट्टा समय से पहले रद्द करने का निर्णय बिल्कुल सही : हाईकोर्ट

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने पत्थर खनन पट्टे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में याचिकाकर्ता आनंद कुमार सिंह को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने रॉयल्टी की राशि का भुगतान न किए जाने को गंभीर मानते हुए खनन पट्टा समय से पहले रद्द किए जाने के निर्णय को सही ठहराया है। यह मामला पलामू जिले के चपरवार मौजा में स्थित पत्थर खनन पट्टे से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2014 से 10 वर्षों के लिए आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता को पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति भी प्राप्त थी। हालांकि, वर्ष 2016 से 2019 के बीच खनन रॉयल्टी का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप सामने आया। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा 30 दिन का नोटिस जारी किए जाने का दावा किया गया।

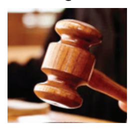

22 नवंबर की शाम रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र से गुम हुआ था बच्चा

61 दिनों के बाद कोडरमा में मिला रांची से लापता कन्हैया, अपहरण या गुमशुदगी, उलझ गई पुलिस

PHOTON NEWS KODERMA : 61 दिनों के बाद रांची के ओरमांझी के रहने वाले 12 साल के कन्हैया को पुलिस ने सोमवार को कोडरमा से बरामद कर लिया है। चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखाड़ी से बच्चों को बरामद किया गया। वह 22 नवंबर की शाम रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र से लापता हुआ था। बच्चे की बरामदगी के बाद पूछताछ में उसने बताया कि वह हाजीपुर अपनी नानी घर चला गया था। वहां से ओरमांझी लौटते समय बस किराया नहीं दे पाने के कारण उसे बस वाले ने चंदवारा के जामुखाड़ी में उतार दिया। इसके बाद वह भटकते हुए राजा कुमार के पास पहुंच गया।

पूछताछ में बच्चे ने बिहार के हाजीपुर में अपनी नानी के घर रहने की कहीं बात

सत्यापन के बाद चंदवारा पहुंची ओरमांझी पुलिस

चंदवारा थाना पुलिस को उरवां इलाके में एक गुमशुदा बच्चे के होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। इसके बाद बच्चे की तस्वीर जिले के पुलिस कप्तान अनुदीप सिंह को भेजी गई। एसपी ने तत्परता दिखाते हुए तस्वीर रांची के एसएसपी राकेश रंजन को भेजी, जहां से पुष्टि हुई कि यह बच्चा ओरमांझी से लापता कन्हैया कुमार ही है। सत्यापन के बाद ओरमांझी पुलिस चंदवारा थाना पहुंची।

जो कहा था, वह करके दिखाया : हेमंत सोरेन

झारखंड सरकार ने जो कहा था, वह करके दिखाया। यह बात सीएम हेमंत सोरेन ने अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह के पर्दाफाश करने को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राज्य में सक्रिय अपराधी गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी और उनकी सरकार ने यह करके दिखाया। दरअसल, रांची पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाते थे।

डरा-सहमा हुआ है बच्चा : बरामदगी के बाद बच्चा घबराया हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि कन्हैया को चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखाड़ी से बरामद किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे का अपहरण हुआ था या खुद से लापता हुआ था। बच्चा डरा-सहमा हुआ है। बच्चे को पुलिस ने उसके मां को सौंप दिया है।

यूपी में दिनदहाड़े घर में घुस कर एक परिवार के चार लोगों की हत्या

ETAH : उत्तर प्रदेश में जनपद एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। दिनदहाड़े घर में घुस कर हत्या की वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे ने बताया कि थाना कोतवाली नगर अंतर्गत ग्राम नगला प्रेमी में एक घर में रह रहे एक वृद्ध, उनकी पत्नी, बहु और नातिनी की अज्ञात हमलावार ने दिन में घर में घुसकर ईंट से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में वृद्ध गंगा सिंह (75) उनकी बहू रत्ना पत्नी कमल सिंह (45), नातिनी ज्योति (20) की मौके पर ही मौत हो गई।

गिरिडीह में फांसी के फंदे पर लटकी मिली मां-बेटी की डेड बॉडी

PHOTON NEWS GIRIDIH : सोमवार को गिरिडीह में घर के एक कमरे में मां-बेटी की फांसी के फंदे पर लटकी लाशें मिलीं। घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर गांव की है। परिजनों ने दोनों के सुसाइड करने की आशंका जाहिर की है। महिला के पति सोनू राम के अनुसार, लोन लेने के बाद से वसूली के लिए आ रहे फोन कॉल से वो परेशान थी। इस घटना की जानकारी परिजनों को सुबह में हुई। मृतका की पहचान पुतुल देवी (35) और बेटी स्नेहा कुमारी (15) के रूप में की गई है। मृतिका के पति टेम्पो चालक हैं। स्नेहा कुमारी 10वीं की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार, पुतुल देवी ने किसी महिला स्वयं सहायता समूह से लोन लिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने परिवार को नहीं दी थी।

- मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर गांव में हुई घटना
- परिजनों को सुबह मिली घटना की जानकारी आत्महत्या करने की जताई आशंका
- पति ने कहा- लोन लेने के बाद से वसूली के लिए आ रहे फोन कॉल से थी दिक्कत

पूछने पर साझा नहीं करती थी परेशानी

सोनू राम ने बताया कि पुतुल देवी अक्सर तनाव में रहती थीं और कई बार रोती भी थीं, लेकिन पूछने पर अपनी परेशानी साझा नहीं करती थीं। परिजनों को इस घटना की जानकारी उस समय हुई, जब सोमवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर जब दरवाजा खोला गया तो मां और बेटी को घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। सूचना पाकर सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव और मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर गांव में दो लोगों द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर पर सुनवाई

1.25 करोड़ वोटर्स को अपना नाम जुड़वाने का मिला एक और मौका

NEW DELHI @ PTI : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 1.25 करोड़ वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया। कहा कि वे 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान नाम, सरनेम, आयु में गड़बड़ी की वजह 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कहा चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक लगाए, ताकि लोगों को पता चल सके। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने कहा- सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता है।

एक लाख क्विंटल के लक्ष्य का 50% किया हासिल, समय पर हुआ भुगतान

धान खरीद के मामले में प्रदेश में नंबर वन बना कोडरमा, भर गए पैक्स गोदाम

PHOTON NEWS KODERMA : पूरे झारखंड में किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में कोडरमा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। धान क्रय में कोडरमा जिला पूरे प्रदेश में नंबर वन पर है। जिले को मिले एक लाख क्विंटल धान क्रय के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 50 प्रतिशत धान की खरीद की जा चुकी है। इस वर्ष धान क्रय के साथ ही किसानों को उनके बैंक खाते में समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। इसके बावजूद पैक्स स्तर पर धान क्रय की प्रक्रिया फिलहाल प्रभावित हो रही है। जिले में इस बार धान क्रय के लिए कुल 30 पैक्स एवं दो महिला मंडलों का चयन किया गया है। 15 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीद में अब तक करीब 50 हजार क्विंटल धान किसानों से खरीदा जा चुका है। इनमें से लगभग 20 हजार क्विंटल धान मिलरों को भेजा गया है। लेकिन, बीते एक सप्ताह से अधिकांश पैक्सों में धान क्रय लगभग ठप है।

क्रय के लिए 30 पैक्स और दो महिला मंडलों का किया गया है चयन

सेहत की चिंता | सामान्य तौर पर थकान के कारण उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति

नींद में रोजाना तेज खर्राटे को नजरअंदाज करना नुकसानदायक

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : मानव शरीर वैज्ञानिकों के अनुसार, 10 अलग-अलग प्रणालियों से मिलकर पूरे शरीर की कार्य प्रणाली संतुलित रूप से चलती है। इन प्रणालियों में आपसी समन्वय अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। किसी भी प्रणाली में विकार आने पर दूसरी प्रणाली भी प्रभावित होती है। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों से अंग प्रभावित होते हैं। इसके कारण सेहत में कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं। इन प्रभावों में कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के भी संकेत छिपे होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नींद के समय सामान्य तौर पर खर्राटे लेना आम बात होती है। थकान की वजह से आम तौर पर खर्राटे आते हैं। लेकिन, प्रतिदिन तेज खर्राटे लेना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है। रांची के जाने-माने चिकित्सक डॉ. अरुण सरकार के अनुसार, नींद के समय रोजाना तेज खर्राटे ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि हर खर्राटा ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं होता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति की सही जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि बीमारी गंभीर है या नहीं और वह किन कारणों से खर्राटे ले रहा है।

असामान्य अवस्था आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली में समन्वय की कमी का परिणाम

गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत, जांच से पता चलेगी ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया

- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया में लगातार उत्पन्न होते हैं तेज आवाज वाले खर्राटे
- शिथिल हो जाते हैं गले के पीछे के मसल्स, वायु के आने-जाने के मार्ग में आती है रुकावट

- मरीज को सोते समय बार-बार सांस रुकने और शुरू होने जैसा होता है महसूस
- अत्यधिक धूम्रपान करने वाले और मोटे लोगों के साथ गंभीर हो सकती है समस्या

हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक की भी स्थिति

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नींद संबंधी विकार है। इसमें तेज आवाज वाले खर्राटे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि नींद के दौरान गले के पीछे की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इससे वायु के आने-जाने के मार्ग में रुकावट आती है। डॉ. सरकार ने बताया कि ऐसी स्थिति में मरीज को सोते समय बार-बार सांस रुकने और शुरू हो जाने जैसा महसूस होता है। कई बार मरीज नींद से उठकर हांफने लगता है। इसके अलावा ज्यादा नींद आना, थकावट, सिर दर्द रहना, मुंह सूखना, रात में बार-बार पेशाब आना, चिड़चिड़ापन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आम तौर पर अधिक वजन वाले लोगों में खर्राटे की समस्या होती है। गर्दन के आसपास अतिरिक्त फैट वायु मार्ग को संकरा कर सकता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, उन्हें खर्राटे आने की समस्या अधिक हो सकती है, क्योंकि धूम्रपान गले और फेफड़ों में सूजन पैदा करता है।

बड़बिल के बैंक में 5 करोड़ की डकैती

CHAIBASA : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से सटे ओडिशा के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में सोमवार को हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। छह बदमाश बैंक में घुसे और कर्मचारियों को बंधक बनाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण तथा लगभग पांच लाख रुपये नकद ले गए। बताया जाता है कि बदमाश ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए और सीधे मैनेजर के चैंबर में पहुंच गए। उन्होंने बंदूक की नोक पर मैनेजर को धमकाया। इसके बाद ग्राहकों और बैंक स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए और लॉकर की चाबी मांग ली। फिर गैंग ने लॉकर से सोने के गहने और नकदी समेट लिए। चश्मदीदों ने बताया कि लुटेरों ने अपने चेहरे नहीं ढके थे। वे ओड़िया और हिंदी दोनों भाषाओं में बात कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बड़बिल थाने की पुलिस तो पहुंची ही, क्योंझर के एसपी भी पहुंचे।

दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में हुई नॉमिनेशन प्रक्रिया

भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन, घोषणा आज

NEW DELHI @ PTI : भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने कहा- इस पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सभी वैध पाए गए। अब नितिन के नाम का औपचारिक ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी राज्यों के सीएम और सीनियर नेताओं ने नितिन के समर्थन में नामांकन पत्र जमा किया था। भाजपा ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था।

बोकारो में हाथी ने ओमनी कार से खींचकर युवक को मार डाला

सब्जी बेचकर घर लौट रहा था रामगढ़ का युवक, सड़क पर था हाथियों का झुंड

PHOTON NEWS BOKARO: बोकारो जिले के महुआटांड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जिले के गोमिया प्रखंड के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में हाथियों ने एक ओमनी कार को रोक लिया और फिर एक हाथी ने कार से एक युवक को खींचकर उसे मार डाला। घटना कंडेर मुख्य सड़क पर सिमरबेड़ा महतो टोला के पास की है। बताया जा रहा है कि इलाके में कई दिनों से हाथियों का आतंक है। इलाके के लोग दहशत में हैं।

हाथियों के हमले में दुर्घटनाग्रस्त कार

रविवार की रात को रामगढ़ का रहने वाला रविंद्र दांगी सब्जी बेचकर अपनी ओमनी कार से घर कंडेर लौट रहा था। सिमरबेड़ा महतो टोला के पास सड़क पर हाथियों का झुंड खड़ा था। हाथियों ने जैसे ही कार को देखा, नजदीक पहुंचकर हमला कर दिया। हाथियों ने कार के अंदर से रविंद्र दांगी को बाहर निकाला और खेतों की तरफ ले जाकर मार डाला। यही नहीं, हाथियों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

लोगों ने रविंद्र को पहले ही किया था आगाह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविंद्र दांगी जब कार लेकर आगे बढ़ रहा था। तो पहले ही लोगों ने उसे आगे जाने से मना किया था। उसे बताया था कि आगे हाथी हैं। लेकिन, लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए रविंद्र दांगी आगे बढ़ गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। सोमवार को मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है।

फायरिंग की कोशिश में राहुल दुबे गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, हथियार बरामद

AGENCY HAZARIBAG : उरीमारी थाना क्षेत्र में फायरिंग की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। यह जानकारी बड़कागांव पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दिया। गिरफ्तार आरोपितों में लातेहार जिले के बालूमाथ के चमातू गांव निवासी राजदीप साव और हजारीबाग जिले के केरेडारी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

निवासी मुनिका कुमारी (20) शामिल है। इनके पास से पुलिस कार्बाइन एक,देशी पिस्टल दो, जिंदा गोली पांच, एके-47 राइफल, मैगजीन चार, एसएलआर राइफल मैगजीन पांच, मोबाइल फोन 06, मोटरसाइकिल 01 (जेएच19डी-7532) बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 18 जनवरी को उरीमारी ओपी क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह की ओर से फायरिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। इस दौरान एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में गिरोह के एक सक्रिय सदस्य राजदीप साव को पकड़ा गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ हथियार महिला आरोपित के घर में छिपाकर रखे गए थे, जहां छापेमारी कर शेष हथियार बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार राहुल दुबे और उसके सहयोगी आशीष साव के निर्देश पर उरीमारी क्षेत्र में कोलियरी कंपनी से रंगदारी की रकम नहीं देने पर फायरिंग की योजना बनाई गई थी। गिरोह के सदस्य पहले कोलियरी क्षेत्र में रेकी कर रहे थे और शाम होने का इंतजार कर जंगल की ओर चले गए थे।

BRIEF NEWS

बैंक मैनेजर के घर से 40 लाख के गहने व कैश चोरी

RAMGARH : रामगढ़ थाना क्षेत्र में पंचवटी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में बैंक मैनेजर के घर में चोरी हुई है। फ्लैट 16 जनवरी से बंद था। चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर लगभग 40 हजार नकद और 35 लाख रुपये के सोना-चांदी के गहने पार कर दिए। घटना की जानकारी फ्लैट मालिक मनीष कुमार को तब हुई, जब वह 18 जनवरी की शाम को घर लौटे। फ्लैट का ताला टूटा हुआ था। अंदर सामान बिखरा हुआ था। आलमारी से नकदी और गहने गायब थे। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी। पता चला कि अपार्टमेंट में लगा सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर कई दिनों से खराब है। मनीष कुमार रामगढ़ की गिद्दी शाखा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों रामगढ़ में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

चतरा में 7 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट

CHATRA : पुलिस अधीक्षक चतरा सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को जिले में अफीम की खेती के उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में सादर थाना अंतर्गत ग्राम संघरी में 2 एकड़ तथा लावालौंग थाना अंतर्गत ग्राम हरहद में 5 एकड़ वन भूमि में की जा रही अफीम की खेती को शुरूआती अवस्था में ही नष्ट किया गया। अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चतरा पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि अफीम की खेती अवैध तरीके से न करें तथा किसी भी व्यक्ति को ऐसी गैरकानूनी गतिविधि करने से रोकने में चतरा पुलिस का सहयोग करें।

बोकारो जिला से अपहृत लड़की हरियाणा से बरामद

BOKARO : बोकारो जिला के पिंड्राजोरा थाना अंतर्गत कुर्रा बाजार से 2 जुलाई 2025 को अज्ञात अपराधी ने एक लड़की को अपहरण कर लिया था। इस मामले में उसी समय सुंदर लाल तुरी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अपहृता की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशानुसार एसडीपीओ-चास प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने मानवीय व तकनीकी सूचना के आधार पर हरियाणा राज्य के मानेसर से अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया। अपहृता वैष्णवी कुमारी की उम्र लगभग 19 वर्ष है। वह पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र स्थित कुरमा गांव की रहने वाली है।

एक करोड़ की चांदी के साथ पकड़ाया चोर गिरोह का सदस्य

GIRIDIH : गिरिडीह पुलिस ने सोमवार को चोरी की चांदी के जेवरात और छह चांदी की सिल्लियों के साथ चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। जब्त चांदी की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. विमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार थाना क्षेत्र में चोरी की चांदी को बेचने की कोशिश की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद एंटी क्राइम जांच के दौरान धनवार इलाके में एक स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से छह चांदी की सिल्लियां, जिनका कुल वजन 32 किलोग्राम से अधिक है, बरामद की गईं। इसके अलावा चांदी के बने पायल, बिछिया, चेन, ब्रेसलेट, पानपत्ता सहित अन्य जेवरात भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, बरामद चांदी की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है। एसपी ने बताया कि इस मामले में कार चालक हजरत अंसारी, निवासी धनवार, को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित चोरी किए गए जेवरातों को धनवार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में बेचने की फिराक में था। चोरी के जेवरातों की बिक्री की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ की जा रही है और इस चोरी में शामिल अन्य गिरोह के सदस्यों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लातेहार बस हादसे के बाद राज्यभर में हुई अलग-अलग दुर्घटनाओं में 9 की चली गई जान

मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10, लगभग 80 लोग घायल

घायलों की स्थिति चिंताजनक, बढ़ सकता मृतकों का आंकड़ा

AGENCY LATEHAR : झारखंड के लातेहार जिले में महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में रविवार को हुई भीषण बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पांच अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान कर ली गई है। मृतकों में सीतापति देवी, प्रेमा देवी, सोनामती देवी, रेशन्ति चेरवा, सुखना भुइयां, विजय नगेसिया, लीलावती सोनवानी, रमेश मनिका, फगुआ राम और परशुराम सोनवानी शामिल हैं। हादसे में लगभग 80 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के अलावा लातेहार और आसपास के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। सभी मृतक और घायल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। दरअसल, रविवार को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक शादी-विवाह के रिश्ते के सिलसिले में लोगों ने बस रिजर्व की थी और महुआडांड़ के लोध गांव आ रहे थे। इसी दौरान ओरसा घाटी के पास बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई की ओर पलट गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बस में सवार लगभग सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम विपिन कुमार दुबे के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एंबुलेंस के साथ-साथ स्थानीय लोगों के निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। इस संबंध में एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि हादसे के बाद सभी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो मरीज ज्यादा गंभीर थे, उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया है।

अस्पताल में इलाजरत घायल

अस्पताल में नवजात शिशु देखने निकले थे दंपती, छिन गया परिवार का सहारा

KODERMA : कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेडीह गांव के पास कोडरमा-जयनगर मेन रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बच्चा मामूली रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोशडीहरा गांव निवासी भागीरथ यादव (30) के रूप में की हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर मरकच्चो से झुमरीतिलैया स्थित एक निजी अस्पताल जा रही थी। वहां उनकी बहन ने हाल ही में एक शिशु को जन्म दिया था, जिसे देखने के लिए दोनों पति-पत्नी अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान पांडेडीह के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल, कोडरमा पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक अपने एक चाचा के द्वादश कार्यक्रम में शामिल होकर लौटा था और रातभर जागा था। परिजनों का अनुमान है कि नींद की झपकी आने के कारण ही बाइक अनियंत्रित हुई होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।

भागीरथ की फाइल फोटो

खाई में गिरी कार, एक की मौत, दो घायल

PHOTON NEWS GIRIDIH : भरकट्टा ओपी क्षेत्र के खेदवारा से समधिन के श्राद्धकर्म में गरुड़पुराण सुनकर एक व्यक्ति रविवार रात करीब 9 बजे अपनी कार से घर चिताखारो लौट रहा था। चिताखरो -खेदवारा नदी पुल के समीप कार (जेएच 10सी9569) असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। घटनास्थल पर कार मालिक सह चालक की मौत हो गई। इसके अलावा कार में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कार खाई में गिरते ही जोरदार आवाज हुई। ठंड में ग्रामीण रात को अपने घर थे। कार की आवाज सुन लोग घर से बाहर निकले, तो देखा कि कार खाई में गिरी हुई थी। कार में सवार लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। ग्रामीणों ने घटना की सूचना ओपी प्रभारी अमन सिंह, मुखिया कंचन देवी के ससुर ईश्वर मंडल, पंसस सुनीता देवी के पति राजू मंडल को दी। घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों के सहयोग से खाई में गिरी कार से चालक समेत दोनों लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद उनकी पहचान हुई। मृतक चिताखारो का सुकर मंडल (58) था। घायलों में वेराहीटांड का मनोज मरांडी (40) व उसके रिश्तेदार हैं। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने सुकर मंडल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग अस्पताल से शव को घर ले गए।

ओपी प्रभारी ने रात को ही शव को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेजा। यहां बता दें कि मृतक सुकर मंडल का समधी चुरामन मंडल का घर भी खेदवारा में ही है। चुरामन मंडल की पत्नी के श्राद्धकर्म में गरुड़पुराण सुनकर रविवार को देर रात सुकर मंडल अपनी कार से घर लौट रहा था कि घर पहुंचने से पहले करीब पौन किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हो गया। सुकर मंडल के तीन पुत्र व एक पुत्री है। सभी बालिग हैं। बड़े पुत्र व पुत्री का विवाह हो चुका है। मृतक की पत्नी जसिया देवी रो-रोकर बेसुध हो जा रही थी।

खाई में गिरी कार

खूंटी में लकड़ी लदा ट्रैक्टर पलटने से दो लोगों की मौत, छह घायल

PHOTON NEWS KHUNTI : रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत निरसिंग गांव के समीप सोमवार को सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब लकड़ी से लदा एक ट्रैक्टर ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों की पहचान रायसोम गांव निवासी मंगल बड़ींग (45) और गुस्सलु बडिंग (60) के रूप में हुई है। वहीं दुर्घटना में घायल हुए लोगों में बिरसु चीक बडाईक कराकेल, चोयता बडिंग, तिलिंगा बडिंग, लोड़गो बडिंग, बुधवा बडिंग और लेचा बडिंग (सभी रायसोम गांव निवासी) शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में सहयोग किया। घायलों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल रनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसोम गांव निवासी लोड़गो बडिंग के अबुआ आवास निर्माण के लिए बगिया बीचाटोली से ट्रैक्टर में लकड़ी लोड कर गांव ले जाई जा रही थी। निरसिंग गांव के पास ढलान पर पहुंचते ही ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर पलट गया। सूचना मिलते ही रनिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी श्यामल कुंभकार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

अस्पताल में इलाजरत घायल

नशेड़ी ने बच्ची से किया दुष्कर्म कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

LATEHAR : लातेहार जिला में सोमवार को हृदयविदारक घटना हुई। इसमें एक दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटना छिपादोहर थाना क्षेत्र की है। पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संतोष सिंह ने सबसे पहले बच्ची को रविवार को ही अपने घर में बंधक बना लिया था। दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची की हत्या कर उसका शव घर से दूर फेंक दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि बच्ची के साथ क्या-क्या हुआ। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने सही समय पर गांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया, वरना गांव की स्थिति बिगड़ सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी संतोष सिंह हमेशा शराब के नशे में धुत्त रहता था। नशे की हालत में ही उसने बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की। बच्ची रविवार से ही गायब थी। परिवार वाले उसकी काफी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन लड़की का पता नहीं चल रहा था।

योजना सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद की बैठक

लातेहार में डीएमएफटी फंड से क्रियान्वित होंगी 9623 विकास योजनाएं

PHOTON NEWS LATEHAR: समाहरणालय सभागार में सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 9623 विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले न्यास परिषद के सदस्यों के समक्ष बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया गया तथा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में विभिन्न योजनाएं जो डीएमएफटी के प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित हैं उनके न्यास परिषद से अनुमोदन के लिए योजनाओं पर सांसद, विधायक लातेहार व विधायक मनिका सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा चर्चा के क्रम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों में डीएमएफटी से पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के प्रति हो रहे कार्य, डीएमएफटी के अंतर्गत ली गई योजनाएं, डीएमएफटी अंतर्गत ली जाने वाली नई योजनाओं के अनुमोदन आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समिति द्वारा 9623 प्राप्त प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सांसद ने कहा कि डीएमएफटी निधि का उपयोग खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लातेहार के विधायक प्रकाश राम, मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह, उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, प्रभारी पदाधिकारी डीएमएफटी समीर कुल्लू एवं खनन प्रभावित प्रखंडों के प्रमुख, उपप्रमुख व मुखिया उपस्थित थे।

समाहरणालय सभागार में बैठक करते पदाधिकारी

डीएमएफटी के प्रावधान

इस दौरान उपायुक्त ने सभी सदस्यों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश, डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि, कौन-कौन सी योजनाओं को लिया जा सकता है, उसकी जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी की राशि खनन से प्रभावित पंचायत क्षेत्रों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से) प्रभावित हो रहा है, वहीं किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है। चयन के समय उच्च एवं निम्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखना है। उपायुक्त ने सांसद, विधायक एवं अन्य सदस्यों को जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित खनन क्षेत्रों की सूची दी गई।

15 आवासीय व डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाड़ियों में बांटी गई स्पोर्ट्स किट

LATEHAR : लातेहार जिला खेल कार्यालय द्वारा संचालित जिले के कुल 15 आवासीय एवं डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाड़ियों के बीच परियोजना निदेशक आईटीडीए प्रवीण कुमार गगराई एवं जिला खेल पदाधिकारी अविनेश कुमार त्रिपाठी ने खेल किट प्रदान किया। लातेहार जिला में संचालित 3 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं 12 डे- बोर्डिंग क्रीड़ा एवं 01 खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र के कुल 380 खिलाड़ियों को किट प्रदान किया गया। इसमें लातेहार जिला मुख्यालय स्थित आवासीय बालक एथलेटिक्स क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, डे-बोर्डिंग बालक-बालिका वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र, डे-बोर्डिंग बैडमिंटन प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदवा प्रखंड के डे-बोर्डिंग बालक-बालिका फुटबॉल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र, महुआडांड़ के आवासीय हॉकी क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय बालिका एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र महुआडांड़ और डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र, गारू के बालक-बालिका खिलाड़ियों को किट प्रदान किया गया। सभी 380 खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, टी-शर्ट, जूता, जर्सी सेट, हॉकी स्टिक, हॉकी बॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नेट, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉर्क, फुटबॉल आदि भी दिए गए। इस अवसर पर जिला खेल समन्वयक लखेश्वर मंडल, आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक आलोक कुमार सिंह, वॉलीबॉल प्रशिक्षक प्रवीण मिश्रा, हॉकी प्रशिक्षक अमित रंजना मिंज, सरिता एक्का, जीवन किशोर मिंज, सुधीर खाखा, फुटबाल प्रशिक्षक सुमित उरांव, सुरेश उरांव आदि उपस्थित थे।

अबुआ दिशोम बजट को लेकर वित्त मंत्री ने बैंकर्स के साथ किया मंथन

- मांगे गए सुझाव, बैंकों ने अपनी राय से मंत्री को कराया अवगत
- बजट एप के माध्यम से 1550 से अधिक मिले सुझाव
- राज्य के कमजोर तबके के आर्थिक उत्थान में राज्य के बैंकर्स की भूमिका महत्वपूर्ण
- नारी सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता, मंईयां सम्मान योजना प्रभावकारी
- राज्य के कम से कम 100 गांवों को गोद लेने पर बैंकों ने जताई सहमति

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर एफएफपी बिल्डिंग में राज्य के बैंकर्स के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के बैंकर्स सरकार के तीसरे संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कमजोर तबकों के आर्थिक उत्थान में बैंकर्स सरकार के साथ मिलकर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकर्स से प्राप्त सुझावों को इस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में इस बजट का विशेष महत्व है। सरकार चाहती है कि यह बजट यूनिक, मजबूत और जनहितकारी हो।

बैंकर्स के साथ बैठक करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

गांवों के विकास में सरकार का करें सहयोग

वित्त मंत्री ने बैंकर्स से आह्वान किया कि वे राज्य के गांवों के विकास में सरकार का सहयोग करें। प्रत्येक बैंक अपने संसाधनों के अनुसार राज्य के गांवों को गोद ले और वहां महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंक राज्य के कम से कम 100 गांवों को गोद लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस पहल करे।

इनकी रही मौजूदगी

बजट पूर्व गोष्ठी में अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग अमरेंद्र प्रताप सिंह, सचिव (व्यय) वित्त विभाग अबू इमरान, अमित कुमार सचिव (वाणिज्य) वित्त विभाग, वित्त विशेषज्ञ हरिद्वार दयाल, विशेष सचिव वित्त संदीप सिंह सहित राज्य के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित कई पब्लिक और निजी सेक्टर के बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य की आधी आबादी के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य के बैंकर्स सरकार को और अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बैंकर्स द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

BRIEF NEWS

जिला बार एसोसिएशन में सड़क सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित

RANCHI : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सोमवार को सिविल कोर्ट कैंपस में रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार की ओर से रिलेशंस के सहयोग से हुआ। सेमिनार में अधिवक्ताओं के साथ सड़क सुरक्षा विषय पर सकारात्मक परिचर्चा की गई। अतिथियों ने अधिवक्ताओं को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित ड्राइविंग, सीट बेल्ट और हेलमेट के उपयोग की अपील की। बताया गया कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में वीडियो बनाने के बजाय घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाना जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

मारवाड़ महोत्सव में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

RANCHI : झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं मारवाड़ी सहायक समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय मारवाड़ महोत्सव के अवसर पर हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का सोमवार को सफल समापन हुआ। यह शिविर आर.बी.एल. थायरोकेयर, भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत (नई दिल्ली) के सहयोग से लगातार तीन दिनों तक आयोजित किया गया। प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बताया कि शिविर में लगभग 300 लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। इसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, पल्स ऑक्सीजन, वजन, हृदय और हड्डी संबंधी जांच की सुविधा प्रदान की गई।

रांची में जन आरोग्य समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम

RANCHI : राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल परिसर के सभागार में सोमवार को जन आरोग्य समिति (जेएएस) के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, कार्यप्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी की भूमिका से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रीति चौधरी ने बताया कि प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सहिया, महिला ग्राम संगठन की महिलाएं तथा अन्य ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

गोलीबारी में घायल 3 लोगों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

जमीन विवाद को लेकर की गई थी फायरिंग, 6 अरेस्ट, कट्टा बरामद

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में दो दिन पहले हुई फायरिंग घटनाकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 7 खोखा, तीन पिलेट, एक स्कार्पियो और 8 मोबाइल बरामद किया है। बता दें कि पिस्का मोड़ तेल मिल गली के पास 17 जनवरी की रात करीब 9 बजे जमीन और पैसे के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई फायरिंग से इलाके में अफरातफरी मच गई थी। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी।

दिन में भी हुई थी मारपीट : सिटी एसपी ने बताया कि 17 जनवरी को दोपहर में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद मामला वहीं शांत नहीं हुआ और बात मारपीट तक आ पहुंची। इसके बाद शाम को दोनों गुट एकबार फिर से आपसी बातचीत के लिए पिस्का मोड़ के पास जुटे। पहले आकाश सिंह और विकास सिंह अपने साथियों के साथ तीन वाहनों में पहुंचे। कुछ देर बाद संजय पांडेय, रवि यादव और आयुष साह उर्फ बबलू साह भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। बातचीत के दौरान फिर से विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते अधिकारियों के साथ सिटी एसपी

- पंडरा ओपी क्षेत्र में दो दिन पहले हुए फायरिंग कांड का पुलिस ने किया खुलासा
- छापेमारी में एक लोडेड देसी कट्टा, एक कारतूस, 7 खोखे, तीन पिलेट, एक स्कार्पियो और 8 मोबाइल किए गए बरामद
- संजय पांडेय के खिलाफ पूर्व में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े हैं कई मामले

संजय पांडेय का रहा है आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार मुख्य अभियुक्त संजय पांडेय का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में कोतवाली डीएसपी समेत सुखदेवनगर और कोतवाली थाना के कई अधिकारी व जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

दोनों गुटों के लोग हुए थे घायल

इस गोलीबारी में आकाश सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी, जबकि विकास सिंह की छाती और बाएं हाथ में गोली लगी है। वहीं दूसरे गुट के रवि यादव को बाएं हाथ और मुंह के पास गोली लगी। घायलों को इलाज के लिए रिम्स और ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस बाबत पंडरा ओपी में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गिरफ्तार बदमाशों में ये हैं शामिल

सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में संजय पांडेय, आशु कुमार साहु उर्फ बबलू, जुबैर खान उर्फ अजू, संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बाबू, पप्पु साव और रोहित पांडेय शामिल हैं।

रिम्स डायरेक्टर बताएं, अब तक क्यों नहीं हुआ बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण का टेंडर : हाईकोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को राज्य में नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट कनफेडरेशन की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में रिम्स के जवाब पर कोर्ट ने असंतुष्टि जताई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का रिम्स द्वारा अब तक अनुपालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।

खंडपीठ ने रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वह रिम्स में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर टेंडर को पूर्ण करने के लिए उठाए गए कदम को अगली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी निर्धारित की। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए नया टेंडर की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई है। रिम्स ने टेंडर की प्रक्रिया जारी रहने की ही बात कही है। दरअसल, रिम्स की ओर से जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए नया टेंडर निकाला गया है। टेंडर में कंपनियो को आमंत्रित किया गया है। रिम्स में ठोस एवं सूखा कचरा के साथ बायोमेडिकल वेस्ट सहित सभी तरह के कचरे का निष्पादन होना है।

- चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई
- 2 फरवरी को अगली सुनवाई के समय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करना है जवाब

एक्ट के तहत होना चाहिए डिस्पोजल

बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में झारखंड में एनवायरमेंटल प्रोटक्शन एक्ट के तहत बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट रूल को लागू कराने की मांग की है। कहा गया है कि राज्य के अस्पतालों, क्लिनिक, नर्सिंग होम आदि जगहों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होना चाहिए। इसके लिए बायो वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल का प्रावधान झारखंड में लागू होना चाहिए।

भाजपा के दबाव में कई माताओं की गोद सूनी होने से बच गई : आदित्य साहू

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने एक के बाद एक बच्चों की बरामदगी पर झारखंड पुलिस को बधाई दी है। साथ ही कहा कि अंश और अंशिका के बाद रविवार को राज्य के विभिन्न स्थानों से 12 अपहृत बच्चों और सोमवार को सिलदिरी शंकरघाट के कन्हैया कुमार की बरामदगी भाजपा के प्रचंड दबाव और आंदोलन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आंदोलन का नतीजा है कि कई माताओं की गोद सुनी होने से बच गई। अभी सैकड़ों बच्चों को खोज निकालना बाकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का धर्म है जनता का सहारा बनना, गरीबों असहायों की सहायता करना। लेकिन जिस प्रकार से महीनों से राज्य में बच्चा अपहरण करने वाला गिरोह सक्रिय है और राज्य से सैकड़ों बच्चों का अपहरण हुआ है इससे साफ है कि पुलिस सक्रिय नहीं थी। अब पुलिस गिरोह के लोगों के सख्ती से पेश आए तो और भी बच्चों का पता चल जाएगा।

- पुलिस पहले से सक्रिय रहती तो नहीं होता इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का अपहरण

साथ ही अविलंब जमशेदपुर के अपहृत व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी और तिलैया से अपहृत बच्चे का भी शीघ्र पता लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की पढ़ाई, परिजनों की चिकित्सा जांच के साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराए। उन्होंने भाजपा के कार्यकताओं का भी आभार व्यक्त किया, जिनके आंदोलन प्रयासों से अपहृत बच्चे बरामद हो रहे है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितने बच्चे गायब हुए हैं ये सभी गरीब,निर्धन परिवार के बच्चे हैं। ये पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराने में सक्षम तक नहीं होते। कुछ दिनों तक रो बिलखकर परिजन संतोष कर लेते हैं।

जनता दरबार में डीसी ने सुनी समस्याएं, इटकी व सोनाहातू सीओ को शोकॉज

RANCHI : सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से सैकड़ों नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने मामलों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इटकी अंचल के एक मामले में जमाबंदी से संबंधित शिकायत पर उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए शो-कॉज किया। इसके अलावा सोनाहातू अंचल में पंजी-2 सुधार में देरी पर सीओ और संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।

नगर निगम प्रशासक ने किया बस टर्मिनल का निरीक्षण

अपर बाजार में गंदगी फैलाने पर ₹7000 फाइन

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य सरकार की पहल पर रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-12 स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम और जुडको के पदाधिकारियों के साथ बस टर्मिनल का स्थल निरीक्षण किया। 15.33 एकड़ में फैले इस बस टर्मिनल में प्रस्तावित जीर्णोद्धार कार्य को लेकर प्रशासक ने स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति, शौचालयों की साफ-सफाई, बस पड़ाव, एंट्री-एग्जिट, पार्किंग और यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जुडको के अधिकारियों ने बस टर्मिनल के नए ले-आउट और डिजाइन की जानकारी दी। प्रशासक ने निर्देश दिया कि यात्रियों के लिए फ्रेंडली परिसर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

बस टर्मिनल का निरीक्षण करते प्रशासक सुशांत गौरव व अन्य

जी+1 वेंडर मार्केट का विकास

प्रशासक में वेंडर्स के लिए जी+1 वेंडर मार्केट के विकास, ऑटो-टोटो स्टैंड, आकर्षक लैंडस्केपिंग, लाइट, सूचना पट्ट, साइनेज बोर्ड, बाउंड्री वॉल पेंटिंग और भविष्य की आवास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रशासक ने कहा कि बस टर्मिनल का पुनर्विकास जर्जर ढांचे को आधुनिक परिवहन सुविधा में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रांची नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण-मुक्त और जाम-मुक्त बनाने के उद्देश्य से अपर बाजार क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। शहीद चौक से गांधी चौक तक सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए।

कार्यक्रम | बिहार व झारखंड के 68 कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक कार्यशाला का हुआ समापन

केवीके जिला का एकमात्र कृषि शैक्षणिक केंद्र : डॉ. एससी दुबे

PHOTON NEWS RANCHI : आईसीएआर अटारी पटना द्वारा नामकुम के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में बिहार एवं झारखंड के 68 कृषि विज्ञान केंद्रों का तीन दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का समापन सोमवार को हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) जिला स्तर पर किसानों का एकमात्र कृषि से जुडा शैक्षणिक केंद्र है। जहां किसानों को कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार व झारखंड में कृषि उत्थान में केवीके की महती भूमिका है। दोनों राज्यों में कृषि का विस्तार कार्य काफी सराहनीय रहा है। लेकिन बदलते कृषि परिवेश और डिजिटल युग में केवीके को किसानोपयोगी गतिविधियों को वैज्ञानिक रूप-रंग के साथ प्रदर्शित करने की जरूरत है। कुलपति ने डॉ. अंजनी कुमार को सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया।

विशिष्ट अतिथि निसा निदेशक डॉ. ए. कर ने कार्यशाला को केवीके वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान अध्ययन, अनुभव, सीख और तकनीकी साझेदारी का उत्तम स्थान बताया। उन्होंने वैज्ञानिकों को फसल कटाई के बाद उत्पादों के मूल्यवर्धन पर बल दिया। अटारी निदेशक डॉ. अंजनी कुमार ने कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों से मिली नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी को जिले के सभी हितकारकों और बहुतायत किसान तक विस्तार करने की सलाह दी।

दिव्यायन रांची को मिले सबसे अधिक अवार्ड

केवीके की कार्यशाला में बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे व अन्य

वैज्ञानिकों को किया गया सम्मानित

मौके पर आय सृजन, आईसीएआर निधि से अलग कृषि विकास, सीड हब, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, अधिकतम बेहतर प्रत्यक्षण, उन्नत कृषि यंत्र, निकरा, आर्या, जलवायु अनुकूल कृषि उत्थान, फार्म इनोवेशन, टीएसपी प्रत्यक्षण, प्रसंस्करण ईकाई संचालन और देशज तकनीकी उत्थान आदि कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य के लिए केवीके और वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे अधिक चार पुरस्कार केवीके दिव्यायन रांची को मिला। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉ. अजीत कुमार सिंह ने अवार्ड ग्रहण किया। इस केंद्र के मिलेट उत्पाद और धान के देशज तकनीक उन्नयन कार्यक्रम को विशेष रूप से सराहा गया।

नव नियुक्त अंचल निरीक्षकों व कानूनगो ने डीसी से की मुलाकात

RANCHI : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (सीजीएल) के माध्यम से चयनित नव नियुक्त अंचल निरीक्षक (सर्किल इंस्पेक्टर सह कानूनगो) एवं कानूनगो ने सोमवार को समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी नव नियुक्त अधिकारियों से एक-एक कर परिचय प्राप्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह चयन राज्य सरकार की कर्मचारी-केंद्रित एवं दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। झारखंड सरकार निरंतर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मदरसा हुसैनिया के कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को पूर्वी भारत की प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्था तथा माल्टा शैखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी (रह.) की पहली यादगार मदरसा हुसैनिया, हुसैनाबाद, कडरू, रांची का वार्षिक इनामी समारोह संपन्न हो गया। इस अवसर पर वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा समापन समारोह के दौरान कुरआन मजीद की तिलावत, नात-ए-रसूल, भाषण प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दो सौ से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिनमें से जांच और चयन के उपरांत एक सौ से अधिक छात्रों को विभिन्न प्रतियोगितात्मक चरणों में भाग लेने का अवसर मिला। छात्रों ने अपनी शैक्षणिक, बौद्धिक और रचनात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

समाचार सार

निक्को पार्क में बच्चों ने बनाया सपनों का कैनवास

JAMSHEDPUR : बिष्टुपुर स्थित निक्को जुबिली पार्क में रविवार को विशाल आर्ट मेला लगा, जिसमें करीब 500 बच्चों ने कैनवास पर कल्पना के रंग उकेरे।

आरकेएफएल फाउंडेशन व उर्विता संस्था के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद बिद्युत बरण महतो व जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने किया। अंत में विजेता बच्चों को आरकेएफएल के वरीय पदाधिकारियों ने पुरस्कृत किया। विजेता छात्रों में ग्रुप-ए से सोयंती चौधरी, अर्नव सिंह व इमान चटर्जी, ग्रुप-बी से रियांशिका, अंकित व अर्नव, ग्रुप-सी में तियासा पाल, सौम्यदीप बोस व भूमिका कुमारी, ग्रुप-डी से विक्की कुमार, मुस्कान कुमारी व प्रीति महतो क्रमशः श्रेष्ठ रहीं।

कुश मूंधड़ा बने चेस चैंपियन

CHAIBASA : रोटरी क्लब के तत्वावधान में सोमवार को चतुर्थ बैजनाथ मूंधड़ा स्मृति शतरंज प्रतियोगिता हुई।

टाउन क्लब में हुई प्रतियोगिता में कुश मूंधड़ा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक रितेश मूंधड़ा ने बताया की प्रतियोगिता में 84 प्रतिभागी शामिल थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईएएस सिद्धार्थ कुमार ने किया, जबकि इस दौरान शतरंज संघ के महासचिव बसंत खंडेलवाल, क्लब के अध्यक्ष विकास दोदराजका, रोटेरियन सुशील मूंधड़ा, डॉ. वीणा मूंधड़ा, गुरमुख सिंह खोखर, अनिल शर्मा, विक्रम खिरवाल, सुनीत खिरवाल, निर्मल चंद्र त्रिपाठी, विष्णु भूत आदि भी मौजूद थे।

जुगसलाई हादसे में घायल युवक की मौत

JAMSHEDPUR : जुगसलाई में 16 जनवरी को एक पिकअप वैन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में व्यक्ति घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस व्यक्ति ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने जुगसलाई थाने में पिकअप वैन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

तारापदो हत्याकांड : कुणाल ने डीजीपी से की बात

GHATSILA : झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने सोमवार को डीजीपी तदाशा मिश्रा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जमशेदपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी कैरव गांधी के अपहरण और गालूडीह में तारापदो महतो की हत्या मामले पर बात की। कुणाल ने बताया कि डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि दोनों मामलों में पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है। पुलिस के सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही कैरव गांधी सकुशल लौटेंगे। तारपादो की हत्या मामले में भी जिला पुलिस पूरी तत्परता से जुटी है। अपराधी किसी सूरत में नहीं बचेगा।

एनएच-33 पर ओवरलोडिंग के खिलाफ चला अभियान

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले में एनएच-33 पर सोमवार को ओवरलोडिंग के खिलाफ सघन जांच अभियान चला, जिसमें 15 वाहनों से लगभग 2.45 लाख रुपये का फाइन वसूला गया।

जिला मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) सूरज हेंब्रम के नेतृत्व में यह अभियान बहरागोड़ा से जमशेदपुर के बीच चला, जिसमें बस समेत 40 छोटे-बड़े वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की जांच की गई।

महाराणा प्रताप को किया नमन

JAMSHEDPUR : विश्व हिंदू परिषद की जमशेदपुर महानगर इकाई ने सोमवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी।

मेरीन ड्राइव गोलचक्कर पर महाराणा की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में विहिप के सिंहभूम विभाग मंत्री अरुण सिंह, जमशेदपुर महानगर के मंत्री चंद्रिका भगत, बजरंगदल के संयोजक चंदन दास, दुगार्वाहिनी की संयोजक ज्योत्स्ना सरकार, गौ रक्षा प्रमुख मनीष सिंह, हिंदूपीठ के महासचिव दिलजय बोस आदि भी शामिल थे।

ताइक्वांडो के खिलाड़ी किए गए पुरस्कृत

JAMSHEDPUR : स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के ट्रस्टी अशोक गोयल व उनकी पत्नी प्रमिला गोयल ने सोमवार को ताइक्वांडो में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

बारीडीह स्थित ट्रस्ट के कार्यालय में जिन प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए, उनमें आशिया कुमारी, रिद्धि चटर्जी, रश्मि गोप, ऋषिका वर्मा, पृथ्वीराज व अमित गोप शामिल थे। यह प्रतियोगिता 24-25 दिसंबर को हुई थी।

साकची बाजार की दो दुकानों से बरामद किया गया 20 पेटी डेंड्राइट व व्हाइटनर

नशेड़ी की सूचना पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, मारा छापा

PHOTON NEWS JSR : साकची में पुलिस ने बाजार की दो दुकानों में छापेमारी कर करीब 20 पेटी डेंड्राइट और व्हाइटनर जब्त किया है। पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह रेड सोमवार की शाम लगभग 4 बजे डाली गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि साकची के टैंक रोड पर मिनरल वाटर की एक दुकान में नशे की सामग्री मिलती है। इस पर साकची थाना की पुलिस ने यहां छापामारी की। छापामारी में दुकान से बड़े पैमाने पर डेंड्राइट और व्हाइटनर बरामद हुआ। इन दोनों का प्रयोग नशे के लिए भी किया जाता है। पुलिस ने मछली बाजार के पास भी एक दुकान में छापामारी की है। यहां से भी बड़ी संख्या में नशे का सामान (डेंड्राइट, व्हाइटनर आदि) बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। दोनों दुकानों से तीन टेंपो में भरकर नशे की सामग्री ले जाई गई है। गौरतलब है कि एसएसपी पीयूष पांडे के आदेश पर पुलिस जिले भर में मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चला रही है।

साकची थाना में टेंपो से जब्त पेटियां उतारते पुलिसकर्मी • फोटोन न्यूज

सोनारी में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहा युवक हुआ अरेस्ट

JAMSHEDPUR : सोनारी थाना की पुलिस ने आशियाना गार्डन के पास चपलू गैस मैदान से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहा एक युवक गिरफ्तार किया। युवक के पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चपलू गैस मैदान के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर छापामारी कर श्याम ठाकुर नामक युवक को पकड़ा। वह सोनारी के परदेसी पाड़ा में सिनेमा मैदान के पास का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने वह ठिकाना बताया, जहां से वह ब्राउन शुगर खरीदता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी है।

सिदगोड़ा में 100 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

हिरासत में आरोपी व जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : सिदगोड़ा थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को एग्रिको रोड नंबर–3 पर भालूबासा के पास खंडहर बन चुके क्वार्टर में छापामारी की। यहां पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 100 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी इलाके में ब्राउन शुगर की खरीद–बिक्री करते थे। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायानगर निवासी प्रीति कुमारी और बागुन नगर टीओपी रोड नंबर 3 का रहने वाला राहुल सांडिल हैं। पुलिस को उनके पास से ब्राउन शुगर के अलावा 5460 रुपये नकद भी मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में तैनात एसआई विकास कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि उनके इलाके में जो भी ब्राउन शुगर बेचता पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा।

टाटा-पटमदा मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में आठ घंटे जंगल में बेहोश रहा युवक, मौत को मात देकर लौटा

भुइयांसिनान में टुसु मेला देखकर घर लौट रहा था रोहन सिंह, कार से हुई थी टक्कर

PHOTON NEWS JSR : पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा-पटमदा मुख्य सड़क पर रविवार रात कड़कड़ाती ठंड में एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पटमदा के धूसरा में जाहिर स्थान के समीप कार और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद जहां वाहन के कल-पुर्जे टूकडे टूकडे गए, वहीं बाइक सवार युवक रातभर लापता रहा। करीब आठ घंटे बाद सोमवार सुबह घायल अवस्था में उसके मिलने पर पूरी घटना की परतें खुलीं। रविवार रात करीब आठ बजे हुई इस दुर्घटना में बाइक और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का अगला चक्का तक अलग होकर सड़क पर जा गिरा। हादसे के बाद कार सवार लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बाइक चालक मौके से गायब हो गया। सूचना मिलते ही पटमदा पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार व बाइक को जब्त कर छानबीन शुरू की। पटमदा थाना प्रभारी करमपाल भगत के नेतृत्व में स्थानीय झामुमो नेता हरिहर सिंह, बामनी निवासी धर्म किस्कू और ग्रामीणों ने देर रात तक घायल बाइक चालक की तलाश की। मुख्य सड़क से लेकर आसपास के जंगल और झाड़ियों में टॉर्च की रोशनी में तलाशी अभियान चला, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला।

आपबीती सुनाता रोहन

इससे पुलिस के साथ-साथ स्थानीय लोग भी चिंतित रहे। सोमवार सुबह करीब आठ बजे अचानक घायल अवस्था में एक युवक मुख्य सड़क पर दिखाई दिया। वह बारूडीह निवासी 19 वर्षीय रोहन सिंह था, जो चंदन सिंह की बाइक पर सवार होकर ठनठनी घाटी स्थित मां काली होटल पहुंचा। होटल में मौजूद लोगों को देखकर उसने पूरी आपबीती सुनाई और कहा कि किस्मत ने उसे नया जीवन दिया है। रोहन के अनुसार वह अपने तिलाईटांड़ (सारी) स्थित घर से एक परिचित की बाइक लेकर भुईयांसिनान टुसू मेला गया था। लौटते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने ओवरटेक करते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे वह संतुलन खो बैठा और जमशेदपुर की ओर जा रही कार से भिड़ गया। हादसे के बाद वह बुरी तरह घबरा गया और जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। डर और चोट के कारण रोहन चिटाबुरु जंगल में काफी देर तक छिपा रहा। सड़क किनारे पुलिस द्वारा टॉर्च से तलाशी अभियान चलने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। इस दौरान सबर टोला की ओर जाने की कोशिश में चोटों के कारण वह बेहोश हो गया और कड़ाके की ठंड में करीब आठ घंटे तक जंगल के पास पड़ा रहा। सुबह होश आने पर किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंच सका। धर्म किस्कू ने बताया कि रोहन पूर्व में मां काली होटल में काम कर चुका है। करीब डेढ़ महीने पहले वह मजदूरी के लिए कर्नाटक गया था और टुसू पर्व में घर लौटा था। रविवार की रात यह हादसा हो गया। सुबह नौ बजे के बाद उसे अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया।

बर्मामाइंस में बढ़ रहा नशे का कारोबार, भाजपा ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

JAMSHEDPUR : भाजपा, बर्मामाइंस मंडल के अध्यक्ष रितेश झा के नेतृत्व में सोमवार को बर्मामाइंस थाना में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें विभिन्न प्रकार के नशे का बढ़ता कारोबार और इसकी वजह से बिगड़ती विधि–व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुलवंत सिंह बंटी ने थाना प्रभारी दिलीप यादव को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर नशा कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया गया, तो भाजपा द्वारा 15 दिन बाद वृहद आंदोलन किया जाएगा। पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने कहा कि बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर थाना प्रभारी ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे इस अवसर पर सतवीर सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक झा, सूरज सिंह, रविजेंट, सौरभ श्रीवास्तव, राकेश चौधरी व पूर्व महामंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे।

बड़ा रेल हादसा टला, एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आ गईं दो ट्रेनें

एक ही ट्रैक पर आमने-सामने खड़ी ट्रेनें व यात्री • फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावां रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब यात्रियों ने एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों को आमने-सामने आते देखा। जानकारी के अनुसार, मुंबई से हावड़ा जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस और एक लोकल ट्रेन एक ही लाइन पर दिखाई दी, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन परिसर में मौजूद यात्री घबरा गए और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते दोनों ट्रेनें कुछ दूरी पर रुक गईं। इससे दुर्घटना की स्थिति टल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर कैसे आ गईं और इसके पीछे सिग्नल व्यवस्था में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय चूक। यात्रियों ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताई है।

बैठक करते उपायुक्त नितिश कुमार सिंह • फोटोन न्यूज

सरायकेला में 7,217 की जगह 909 किसानों ने ही बेचा धान

JAMSHEDPUR : उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सरायकेला–खरसावां जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 909 किसानों से 52,504.72 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि जिले में कुल 7,217 सक्रिय किसान पंजीकृत हैं। उपायुक्त ने भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की तथा लंबित भुगतान को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों (लैम्प्स) पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद, धान का ससमय उठाव तथा धान विक्रय के उपरांत किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही एडवांस सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) के जेनरेशन एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसानों का धान लैम्प्स में सुचारू रूप से विक्रय हो, इसका ध्यान रखा जाए। इनेक्टिव किसानों को सक्रिय करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, लैम्प्स से धान का ससमय उठाव हो तथा गोदाम क्षमता में वृद्धि के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सरकारी भवनों को चिह्नित कर विभाग को सूची भेजें। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखते हुए दस्तावेजों का समयबद्ध संधारण, डेटा का नियमित अद्यतन एवं सतत अनुश्रवण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य का प्रभावी, समयबद्ध एवं लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बछड़ों की लगी प्रदर्शनी पशुपालक हुए पुरस्कृत

कार्यक्रम में सम्मान ग्रहण करता बछड़े का मालिक • फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य योजना के तहत गोवंश एवं गव्य नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को बछड़ा प्रदर्शनी एवं गव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गोलपहाड़ी स्थित जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में 53 बछड़ों ने भाग लिया। निर्णायक मंडली द्वारा वैज्ञानिक मानकों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए 3 प्रगतिशील पशुपालकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि अन्य 7 पशुपालकों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी थे। अंत में पशुपालकों से अपील की गई कि वे इस प्रदर्शनी से प्राप्त अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान को अपने पशुपालन कार्य में अपनाकर उन्नत, वैज्ञानिक एवं लाभकारी पशुपालन की दिशा में आगे बढ़ें और जिले के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

क्राइम ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के तहत सारंडा होगा नक्सली मुक्त, नक्सलियों के खात्मे की अंतिम तिथि नजदीक

सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे चाईबासा, मैराथन बैठक में बनाई गई रणनीति

PHOTON NEWS CHAIBASA : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने की डेडलाइन मार्च 2026 रखी है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक (ऑपरेशन) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने सारंडा क्षेत्र में चल रहे ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को लेकर सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ सारंडा की लड़ाई को मजबूती के साथ जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। पुलिस का दावा है कि जो समय सीमा निश्चित की गई है, उस समयसीमा में झारखंड से भी नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि 2 घंटे तक चली बैठक में पत्रकारों का कोई भी सवाल का जवाब दिए बिना डीजी निकल गए।

चाईबासा पहुंचे सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह • फोटोन न्यूज

केंद्रीय बलों के समन्वय से नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य : एसपी

पुलिस अधीक्षक अमित रेनु ने कहा कि झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ समन्वय स्थापित कर नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। इसको लेकर आज सीआरपीएफ के डीजी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आगे भी ठोस रणनीति के आधार पर मिलकर काम किया जाएगा। सारंडा से नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।

सारंडा माओवादियों का गढ़

झारखंड का कोल्हान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गुट डेरा डाले हुए है, जिसमें तीन एक–एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। कोल्हान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल (तीनों एक करोड़ के इनामी), मोछू, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अप्टन, जयकांत, रापा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए जमा हैं।

2025 से अब तक कई ब्लास्ट, जवान भी हुए हताहत : पश्चिमी सिंहभूम जिला में मार्च 2025 से लेकर अब तक नक्सलियों द्वारा दो दर्जन से अधिक बार ब्लास्ट किए जा चुके हैं। 12 मई 2025 को हुए ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते के आरक्षी मनोज कुमार दमाई बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाकर इलाज करवाया जा रहा है।इससे पहले 5 मार्च को हुए ब्लास्ट में तीन जवान घायल हुए, 16 मार्च के ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ, जबकि 22 मार्च को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए। वहीं सीआरपीएफ के ही हेड कांस्टेबल घायल हो गए। 13 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए। वहीं पिछले तीन सालों में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में एक दर्जन से अधिक ग्रामीण मारे गए हैं, जबकि दर्जनों घायल भी हुए हैं। दो हाथी और एक दर्जन से अधिक जानवर भी मारे गए हैं।

आईईडी ब्लास्ट बना नक्सलियों का हथियार : कोल्हान में नक्सली अपने वजूद की आखरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में वे किसी की भी बलि लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में नक्सलियों का एकमात्र मकसद है कि किसी भी तरह अपने ठिकानों तक पुलिस न पहुंचने दे।पुलिस से बचने के लिए कोल्हान के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने आईईडी बमों का ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है, जिसे भेदने में झारखंड पुलिस अब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। आईईडी बमों की चपेट में आने से ग्रामीणों की जान जा रही है, उनके पशु भी विस्फोट में मारे जा रहे हैं। जंगल में जाना ग्रामीणों के लिए मजबूरी है, तो वहीं नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के लिए भी जंगलों में उतरना बेहद जरूरी।ऐसे में ग्रामीणों और सुरक्षा बलों दोनों का ही आईईडी बमों से सामना हो रहा है।

झारखंड में नक्सलियों का सबसे मजबूत दस्ता फिलहाल सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट में डेरा डाले हुए है। 15 हजार से ज्यादा सुरक्षाबल नक्सलियों को घेरने के तैयार हैं, लेकिन मार्च 2026 तक माओवादियों के सफाए को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे सुरक्षाबल हर हाल में सारंडा फतह करने में आर-पार करने की ठान चुके हैं।

केयू में सीनेट का चुनाव 22 को, दोपहर 1 बजे तक मतदान

JAMSHEDPUR : कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण हेतु वर्ष 2026 का चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर विवि लगातार तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह डीएसडब्ल्यू डॉ. संजय कुमार यादव ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर नियुक्त सभी चुनाव पदाधिकारियों के साथ बुधवार को ऑनलाइन बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू होगी। बैठक में डॉ. रंजीत कुमार कर्ण, डॉ. राजेंद्र भारती, डीन कॉमर्स, डीन साइंस सहित विश्वविद्यालय स्तर के चुनाव पदाधिकारी एवं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे।

BRIEF NEWS

नालंदा में अधेड़ की डैम में डूबकर मौत

NAVADA : बिहार में नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली पंचायत स्थित गोपालपुर डैम में सोमवार को एक हादसे में अधेड़ व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़ दिबौर गांव निवासी 52 वर्षीय सुरेश सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सुरेश सिंह शौच के लिए डैम किनारे गए थे। इसी दौरान पानी में हाथ धोते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना पर रजौली थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के निर्देश पर एसआई संगीता कुमारी ने शव को कब्जे में लेकर नवादा सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

मोबाइल और ई-मेल के माध्यम से पुलिस से सीधे जुड़ेंगे आम नागरिक

SARAN : सरकार की 'सात निश्चय योजना' को धरातल पर उतारने और पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय के निदेर्शानुसार वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी थानों की गश्ती गाड़ियों पर अब संबंधित थाने का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अंकित किया जा रहा है। अक्सर आम नागरिकों की यह शिकायत रहती थी कि आपात स्थिति में या किसी सूचना को साझा करने के लिए वे सीधे पुलिस तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसी समस्या के स्थाई समाधान के लिए एसएसपी ने यह पहल शुरू की है। अब गश्ती के दौरान सड़कों पर दौड़ती पुलिस की गाड़ियों को देखते ही नागरिक उस पर लिखे नंबरों के जरिए अपनी बात रख सकेंगे।

डॉ. किरण ओझा बने आईएमए छपरा के नए अध्यक्ष

SARAN : छपरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छपरा शाखा के शासी निकाय का चुनाव उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए आयोजित इस चुनाव में जिले के चिकित्सकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही संगठन के नए नेतृत्व की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है। नई कार्यकारिणी की गठन के अनुसार डॉ. किरण ओझा को आईएमए छपरा का नया अध्यक्ष चुना गया है। संगठन के सुचारू संचालन के लिए डॉ. सुधांशु शेखर को सचिव के महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारिणी में अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गईं, जिनमें डॉ दीपक कुमार को संयुक्त सचिव, डॉ. तौसीफ मूर्तजा को वित्त सचिव, डॉ. महिमा पाण्डेय को क्लीनिकल सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया।

समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी को दी सौगात

मुख्यमंत्री ने किया 41 योजनाओं का शिलान्यास व 26 का उद्घाटन

AGENCY SITAMADHI : समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सीतामढ़ी के बेलसंड में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने 346 करोड़ रुपये से निर्माण होने वाली 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208.12 करोड़ के लागत से पूरी हुई 26 योजनाओं का उद्घाटन किया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में क्रियान्वित विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, निरीक्षण व जनसंवाद किया। उक्त सभी कार्यक्रम बेलसंड में आयोजित हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे।

मुख्यमंत्री पटना से हेलीकॉप्टर से बेलसंड पहुंचे थे। इस दौरान पहले कार्यक्रम के रूप में सीएम ने 7089.38 लाख रुपए से बने बेलसंड-मीनापुर पथ के चंदौली घाट पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल व पहुंच पथ निर्माण का उद्घाटन किया।

शिवहर को 59 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के तहत राज्य के सबसे छोटे शिवहर जिले में पहुंचे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनता का धन्यवाद देने के उद्देश्य से निकले हैं। सीएम ने शिवहर के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है।

शिवहर में मुख्यमंत्री ने 59 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। यहां 42 करोड़ रुपये की लागत से 75 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 17 करोड़ रुपये की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की प्रगति को नई गति देने का संकल्प जताया है।

सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 554 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। इसमें 346 करोड़ रुपये की लागत से 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208.12 करोड़ रुपये की लागत से 26 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये योजनाएं कल्याणकारी और विकास से जुड़ी हैं, जो जिले के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को मजबूत करेंगी। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा, वे जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिसमें स्थानीय समस्याओं को सुनना और समाधान के आश्वासन शामिल हैं। यह कार्यक्रम लोगों के बीच सरकार की पहुंच को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कुल 9 जिले शामिल हैं।

फिर बागमती तटबंध का निरीक्षण कर हितनारायण उच्च विद्यालय चंदौली के लिए प्रस्थान किया। हितनारायण उच्च विद्यालय में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण आधारित बने नक्षत्र वाटिका व पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस परिसर से ही सीएम नीतीश कुमार ने जिले की योजनाओं का समेकित रूप से शिलान्यास व उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया।

समृद्धि यात्रा के क्रम में सीएम ने सीतामढ़ी में संचालित बोधायन ऑनलाइन लाइव क्लासेस की विशेषता व इसकी उपयोगिता को भी देखा। डीएम रिची पांडेय के पहल पर शुरू की गयी बोधायन क्लासेस का संचालन प्रतिभावान शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें माध्यमिक के छात्र-छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम को लाइव पढ़ाया जाता है।

अगर बात करें सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए योजनाओं के शिलान्यास की तो भवन निर्माण विभाग में 321.93 करोड़ की 37 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग 6.30 करोड़ से एक योजना, अल्पसंख्यक कल्याण में 8.85 करोड़ की लागत से 1 योजना, पुल निर्माण निगम में 7.85 करोड़ में 1 योजना और एलएईओ पुपरी में 1.7 करोड़ की लागत से 1 योजना का शिलान्यास किया गया। पुल निर्माण निगम में 80.44 करोड़ की लागत से 2 योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 2.55 करोड़ की लागत से 5 योजना का उद्घाटन किया गया।

NEWS BOX

अररिया में अंतरराष्ट्रीय फूल दिवस पर बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज के तिरसकुंड पंचायत के प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला मधुरा में सोमवार को बच्चों द्वारा धूमधाम से

अंतरराष्ट्रीय फूल दिवस मनाया गया। बच्चों ने फूल से संबंधित काव्य पाठ कर फुल बगिया में ही अच्छे अपनी भाव भंगिमा प्रस्तुत किया और मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फूल दिवस का मानव श्रृंखला बनाया। मौके पर पूर्व प्रधानाध्यापक कुमार राजीव रंजन ने कहा कि आज के व्यस्त भरी जिंदगी में लोगों को फुर्सत नहीं है। लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। विकास जितना ही होगा विनाश होना निश्चित है। ऐसे में मनुष्य को जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। भूमिगत होते जल के बचाव को लेकर जल का किफायती प्रयोग करने की अपील की। वर्षा जल संरक्षण को आवश्यकता करार दिया। प्रकृति प्रकोप से बचने हेतु ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने और डीजल पेट्रोल का कम-से-कम प्रयोग करने की भी अपील की। जल और हरियाली के बिना किसी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए एवं उसकी देखभाल भी करना चाहिए। मौके पर बच्चों ने अपने कल्पनाशीलता के आधार पर फूलों की पेंटिंग तैयार की। वही प्रधान शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह, शिक्षक रंजीत कुमार मंडल,संजीत कुमार निगम ने भी अपने-अपने विचार रखे तथा बच्चों ने एक दूसरे को फूल देकर स्वागत किया।

स्पोर्ट्स कार्निवाल के बैडमिंटन टूर्नामेंट में किशनगंज चैंपियन

AGENCY ARARIA : बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित स्पोर्ट्स कार्निवाल सीजन वन के बैडमिंटन टूनार्मेंट का चैंपियन किशनगंज

बना। सोमवार को प्रांतीय अध्यक्ष अश्वनी खटोड़ एवं प्रांतीय खेलकूद संयोजक निशांत गोयल ने संयुक्त रूप से उदघाटन किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। पहले दिन 8 प्री-क्वार्टर फाइनल एवं 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतियोगिता के बाद सेमीफाइनल में मुजफ्फरपुर की 2 टीमें, फारबिसगंज की 1 टीम एवं किशनगंज की 1 टीम ने जगह बनाई।पहले सेमीफाइनल में मुजफ्फरपुर ने फारबिसगंज को 2-0 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में किशनगंज ने मुजफ्फरपुर को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला मुजफ्फरपुर एवं किशनगंज के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए किशनगंज की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।

दिघवारा-अंबिका भवानी हॉल्ट के बीच बनेगा आरओबी, जाम से मिलेगी मुक्ति

AGENCY SARAN : सोनपुर-छपरा रेलखंड पर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।

रेल मंत्रालय ने इस रेलखंड पर यातायात की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए सोनपुर मंडल के दिघवारा और अंबिका भवानी हॉल्ट के बीच एक शानदार रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 124.78 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। यह आरओबी वर्तमान लेवल क्रॉसिंग संख्या 16 स्पेशल के स्थान पर बनाया जाएगा। परियोजना की खास बात यह है कि भारी वाहनों के लिए ऊपर से पुल होने के साथ-साथ, स्थानीय निवासियों और छोटे वाहनों की सुविधा के लिए एक लो हाइट सब-वे का भी निर्माण किया जाएगा। यह पुल न केवल रेलवे क्रॉसिंग को पार करेगा, बल्कि एनएच-31ए पटना-छपरा हाईवे को प्रमुख जिला सड़कों से सीधे जोड़ देगा, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बदलाव आएगा। अत्यधिक ट्रैफिक के कारण जब भी ट्रेन गुजरती थी, तो फाटक बंद होने पर सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती थीं। जाम के कारण न केवल आम जनता के समय की बबार्दी होती थी बल्कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं का समय पर निकलना भी असंभव हो जाता था।

छपरा में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की विदेशी शराब जब्त, एक अरेस्ट

AGENCY SARAN : छपरा बिहार में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग टीम को सफलता हाथ लगी है। जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित जयप्रभा सेतु के पास एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को इनपुट मिला था कि उत्तराखंड नंबर के एक ट्रक में शराब की खेप यूपी के रास्ते बिहार लाई जा रही है। मांझी चेक पोस्ट पर जब ट्रक को स्कैन किया गया, तो शातिराना तरीके से छिपाकर रखी गई शराब स्कैनर में पकड़ में नहीं आई। संदेह होने पर उत्पाद विभाग ने स्थानीय पुलिस की मदद ली। मामला तब पुख्ता हो गया जब ट्रक को थाने ले जाते

समय चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे बाजार क्षेत्र से खदेड़कर पकड़ लिया। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद जब ट्रक की सील तोड़ी गई, तो अंदर अंग्रेजी ब्रांड की शराब के सैकड़ों कार्टन में 8316 लीटर बरामद हुए। सहायक आयुक्त मद्य निषेध केशव कुमार झा ने बताया कि शुरूआती पूछताछ में चालक ने खुलासा किया है कि शराब की यह खेप पंजाब से चली थी और इसे मुजफ्फरपुर पहुँचाया जाना था। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अब पकड़े गए चालक से मिली जानकारी के आधार पर पूरे तस्करी सिंडिकेट को खंगाल रही है।

नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

AGENCY PATNA : पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और राज्य में महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इनकम टैक्स चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि राजग शासन में महिलाओं और बच्चियों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा भय का माहौल बना रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपाझ्रजदयू सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और किसी भी गंभीर घटना के बाद पुलिस प्रशासन

पर दबाव डालकर कार्रवाई की गति धीमी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और छात्रा को न्याय दिलाने के लिए जहानाबाद से पटना तक लगातार आंदोलन कर रही है। उप मुख्यमंत्री सह गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे मीडिया में कानून-व्यवस्था और बुलडोजर एक्शन को लेकर बयान देते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि राजधानी पटना ही महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और हॉस्टल संचालिका से पूछताछ के बाद छोड़ दिए जाने पर भी सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस मौके पर कहा कि राजधानी के पॉश इलाके में इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद राजग शासन की पुलिस अबतक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

पर्सनल और ग्रुप लोन के नाम पर कर ली ठगी, खाता खुलवाने के लिए वसूले गए पैसे

AGENCY ARARIA : बिहार में अररिया जिले के फारबिसगंज शहर के शास्त्री चौक कोठीहाट रोड स्थित आरपीएल कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी पर्सनल और समूह लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी कर फरार हो गया।

कंपनी के द्वारा गांव गांव जाकर महिलाओं का समूह बनाया गया और फिर एक लाख रुपए खाता में लोन का पैसा आने के नाम पर खाता खुलवाने के लिए पांच पांच हजार रुपए समूह और पर्सनल लोन के हेतु नया खाता खुलवाने के नाम पर रुपए की वसूली कर रातों रात फरार हो गया।

कंपनी के फरार होने की जानकारी के बाद ठगी के शिकार हुए सैकड़ों लोग सोमवार को पहले कार्यालय पहुंचे और फिर फारबिसगंज थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष को मामले की जानकारी दी। शास्त्री चौक कोठीहाट रोड में कुछ दिन पहले ही आरपीएल कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी का कार्यालय खोला गया था।जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर पर्सनल और समूह लोन कम ब्याज पर दिए जाने का दावा किया गया था। आरपीएल कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के द्वारा बकायदा अनुमंडल क्षेत्र के फारबिसगंज,नरपतगंज और भरगामा के ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर समूह का निर्माण भी किया गया। जिसके बाद प्रति समूह को एक एक लाख रुपए और पर्सनल पचास हजार रुपए तक खाता में आने की जानकारी देकर सभी से नया खाता खुलवाने के नाम पर रुपए की उगाही की गई।

चरस तस्करी मामले में एक को चौदह वर्षों का कठोर कारावास

EAST CHAMPARAN : बिहार में मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए चौदह वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छहमाह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। सजा पलनवा थाना के मुशहरवा निवासी स्व. जगदेव दास के पुत्र पन्नालाल दास को हुई। मामले में रामगढ़वा थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या 21/2023 दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 जनवरी 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ लेकर आ रहा है।

खोदाई में निकले पहली सदी के तिलाधक विश्वविद्यालय का डीएम ने लिया जायजा

AGENCY NALANDA : बिहार में नालंदा जिले के जिलाधिकारी ने नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायती राज तेलहाड़ा ग्राम में खोदाई में निकले पहली सदी के तिलाधक विश्वविद्यालय का जायजा लेने सोमवार को पहुंचे। इस संबंध में दी गई जानकारी के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 453 ईसा पूर्व में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। जबकि तिलाधक विश्वविद्यालय पहली सदी का था। तेल्हारा भ्रमण के दरम्यान मंचीय कार्यक्रम में तत्कालीन मुखिया अवधेश गुप्ता की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 दिसंबर 2009 को तेल्हारा स्थित टीले पर चढ़कर अपने हाथों से खुदाई के काम का

शुभारंभ किया था। खुदाई में सबसे पहले पाल कालीन मूर्तियां निकली थी वहीं बीच में गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष निकले हैं जब गहरी खुदाई की गई तो कुषाणकालीन मूर्तियां और अवशेष मिले हैं। कार्बन डेटिंग में यह ईसा पूर्व का बताया गया है। खुदाई में सैकड़ो मॉनास्ट्री सील, अभिलेख, भगवान बुद्ध अवलोकेतेश्वर, चामुंडा, हरितिका, मां तारा अपराजिता आदि टेराकोटा की मूर्तियों एवं बर्तन मिली। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 630 ई में जब चीन से भारत आया था तो सर्वप्रथम वह नालंदा विश्वविद्यालय से पहले तिलाधक विश्वविद्यालय आया था। उसने तिलाधक संघाराम, महाविहार, सह विश्वविद्यालय का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी भारत यात्रा वृतांत में किया है।

बैठक — नॉर्थ कोयल जलाशय, मंडई वीयर व ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पथ की हुई समीक्षा

मुख्य सचिव ने तय की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की 'डेडलाइन'

AGENCY PATNA : मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को राज्य की तीन परियोजनाओं- नार्थ कोयल जलाशय, मंडई वीयर और ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पथ की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि बिहार की कृषि और कनेक्टिविटी की जीवनरेखा हैं।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को लेकर मुख्य सचिव ने गया के जिलाधिकारी द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर इस परियोजना के महत्व पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि 28 जनवरी तक परियोजना में व्यापक प्रगति

अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत

51.2 किमी के कॉरिडोर का है मामला

कार्य की वर्तमान प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने इसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 51.2 किमी का यह कॉरिडोर समस्तीपुर (ताजपुर) को पटना (बख्तियारपुर) से सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी लगभग 2 घंटे कम हो जाएगी। इस पथ के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। यह मार्ग न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि वैशाली और समस्तीपुर के कृषि उत्पादों को पटना के बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को इस सड़क के किनारे सघन पौधारोपण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और सचिवों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली भू-अर्जन या वन विभाग की एनओसी जैसी समस्याओं का निपटारा अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से तुरंत करें। रैयतों को भुगतान भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सुनिश्चित की जाएगी। यह दशकों पुरानी परियोजना गया और औरंगाबाद जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए वरदान है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि नहरों के नेटवर्क को इस तरह तैयार किया जाए कि खरीफ और रबी, दोनों फसलों के लिए सिंचाई सुनिश्चित हो सके। जिन क्षेत्रों में कार्य की गति धीमी है, वहां कार्य बल बढ़ाने और साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मंडई वीयर परियोजना की सुस्त रफ्तार पर मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण की चेतावनी देते हुए इसके व्यापक लाभों को रेखांकित किया। यह परियोजना फल्गु नदी की सहायक नदियों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जल संचयन और भू-जल स्तर में सुधार करना है। इसके पूर्ण होने से जहानाबाद और आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक आहर-पईन प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

सारण में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

SARAN : आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन को लेकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय सभाकक्ष में हुई इस बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के आलोक में अब तक की गई तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन पूरी भव्यता और अनुशासन के साथ किया जाना है। उन्होंने मुख्य समारोह स्थल राजेंद्र स्टेडियम की साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, और विद्युत आपूर्ति जैसे बुनियादी इंतजामों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी के जनता दरबार में 45 मामलों के निष्पादन का निर्देश

AGENCY SARAN : जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जनता दरबार' का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 45 परिवादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं और शिकायतों को रखा। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी की बातें सुनीं और उनके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दरबार में पहुंचे परिवादियों में सबसे अधिक संख्या राजस्व और भू-अर्जन से संबंधित मामलों की रही। ग्रामीणों ने भूमि मापी, आपसी विवाद और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त कई कर्मियों ने लंबे समय से रुके हुए मानदेय को दिलाने की गुहार

लगाई, राशन कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों और पंचायत स्तर पर 'नल-जल योजना' की अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुखता से दर्ज की गईं।मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई और समयबद्ध निराकरण का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस्लामिक कट्टरपंथ और भारत के प्रति घृणा हावी

बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ यह भी दिख रहा है कि वहां की अंतरिम सरकार भारत से संबंध सुधारने के बजाय बिगाड़ने पर अमादा है। उसे न तो अपने यहां के हिंदुओं की हत्याओं की कोई परवाह है और न ही भारत विरोधी तत्वों के बेलगाम होते जाने की। वह इन तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें शह ही अधिक दे रही है। अपने यहां भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए बांग्लादेश एक ओर जहां अपनी क्रिकेट टीम को भारत में आयोजित होने वाले टी-20 विश्व कप में भेजने में आनाकानी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान से अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। बांग्लादेश में जो हालात हैं, वे हमारी भूलों की भी देन हैं। ऐसी ही भूल हमने कश्मीर को हड़पने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के मामले में भी की थी। कश्मीर को महज एक राजनीतिक समस्या मानकर हम वहां राजनीतिक समाधान तलाशते रहे। इसके परिणाम क्या रहे, उससे सभी परिचित हैं। हमने कोई सबक नहीं सीखा और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लाभाषी मुसलमानों और हिंदू अल्पसंख्यकों का पाकिस्तानी फौज द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने और बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए भारत ने पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ा। जिस समय भारत बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में कूदा, उस समय तक पाकिस्तान की फौज 25 लाख बांग्लाभाषी मुसलमानों और हिंदुओं का नरसंहार कर चुकी थी और लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका था। पाकिस्तान की फौज बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदलने के लिए रेप कैंप संचालित कर रही थी। इन कैंपों में जन्मे हजारों बच्चों के पुनर्वास के लिए बाद में बांग्लादेश की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चलाना पड़ा। लगभग 4000 भारतीय सैनिकों के बलिदान के बाद ये पाशविक अत्याचार बंद हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, परंतु हमने न तो इन अत्याचारों के अपराधी एक भी पाकिस्तानी सैनिक या सैन्य अधिकारियों को सजा दी और न ही इन जनसंहारों और अत्याचारों में पाकिस्तानी फौज का साथ देने वाले स्थानीय जमाती रजाकारों को ही मिटा डालने के लिए कुछ किया। भारत ने सोचा कि बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तानी फौज और जमातियों के इन भयावह अत्याचारों को झेलने के बाद अब कभी भी इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते नहीं चलेंगे और न ही पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कभी सोचेंगे। इसी गलत आकलन के आधार पर बंगाली मुसलमानों के लिए तो भारत ने पूरा नया देश बनाकर दे दिया, परंतु वहां रह रहे हिंदुओं और बौद्धों को एक बार फिर से वहां के मुस्लिम समाज के भरोसे छोड़ दिया। भारत में नीति-निमार्ता भूल गए कि 1946 में बंगाली मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ देते हुए जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी और नोआखाली में हिंदुओं के नरसंहार को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अधिकतर नेता और सैन्य अधिकारी मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी फौज में रह चुके थे। भारत ने पाकिस्तान से अलग होकर बने नए देश बांग्लादेश के नेताओं और सेना पर इतना भरोसा किया कि चटगांव हिल ट्रैक्ट्स जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी बांग्लादेश के कब्जे में ही छोड़ दिया, जबकि 1947 के बंटवारे में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स भारत के हिस्से में आने चाहिए थे, क्योंकि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के अंतर्गत बंगाल का बंटवारा हुआ था और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स उस समय बंगाल का भाग नहीं था। न ही वह मुस्लिम बहुल था, जो पाकिस्तान को दिया जाता। यही कारण था कि वहां की जनता को लगा था कि उनका भारत का भाग बनना निश्चित है और 15 अगस्त, 1947 को वहां तिरंगा लहराया भी गया था, परंतु बंगाल बाउंड्री कमीशन ने अप्रत्याशित रूप में 17 अगस्त, 1947 को चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान की फौज ने वहां से तिरंगा उतारा। 1971 की जीत के बाद भारत चटगांव हिल ट्रैक्ट्स वापस ले सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हम यह दिखाना चाहते थे कि हमने तो सिर्फ मानवता के आधार पर बांग्लादेश की सहायता की है, जबकि चटगांव और त्रिपुरा के बीच में मात्र 28 किमी लंबी पट्टी है, जिस पर भारत का अधिकार होने पर भारत के उत्तर पूर्व को समुद्री तट प्राप्त हो सकता था और वहां का आर्थिक विकास हो सकता था। इसके अलावा चीन और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने से रोका जा सकता था और लाखों बौद्धों एवं हिंदुओं की रक्षा हो सकती थी। आज बांग्लादेश में जो हालात हैं, उससे यह स्पष्ट है कि इस्लामिक कट्टरपंथ और भारत के प्रति घृणा वहां के समाज पर अब उसी तरह हावी है, जैसे पाकिस्तान पर हावी है। वह भारत के एहसान और बलिदान, दोनों को ही भूल चुका है। इसलिए भारत में नीति-निमार्ताओं को आज के बांग्लादेश संकट को पूर्व में शेख मुजीब और जियाउर रहमान की हत्याओं से उपजे राजनीतिक संकटों की तरह समझना बंद कर देना चाहिए। वे हिंसा के बावजूद अंततोगत्वा राजनीतिक संकट थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के समाज का बड़े पैमाने पर जिहादीकरण हुआ है और यदि हमने इस तथ्य की अनदेखी कर उसे राजनीतिक समस्या समझकर उससे निपटने की कोशिश की तो हम वैसे ही पछताएंगे, जैसे कश्मीर के मामले में पछताते आए हैं।

Social Media Corner

सच के हक में...

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के स्थापना दिवस पर, हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनकी व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प संकट के क्षणों में भी अचूक रहते हैं। आपदा आने पर हमेशा सबसे आगे रहकर, एनडीआरएफ कर्मी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीवन की रक्षा करने, राहत प्रदान करने और आशा जगाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उनके कौशल और कर्तव्यनिष्ठा सेवा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वर्षों से, एनडीआरएफ आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में एक मिसाल बनकर उभरा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान अर्जित किया है।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

कोकबोरोक दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह विशेष आयोजन कोकबोरोक भाषा का उत्सव मनाता है, जो हजारों वर्षों से बोली जाने वाली एक प्राचीन, सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्वदेशी भाषा है, और भारत की विविधता और साझा मूल्यों की समृद्धि को उजागर करता है।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के धनबाद की अवैध खदानों से निकलने वाला चोरी का कोयला जीटी रोड के रास्ते बगोदर, गिरिडीह और हजारीबाग होते हुए बड़े पैमाने पर तस्करी के जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से करीब 5000 टन से भी ज्यादा अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का राजनैतिक प्रभाव

ANALYSIS

प्रमोद भार्गव

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का राजनैतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका आकलन करने से पहले इस अभियान के तहत हटाए जाने वाले मतदाताओं का विश्लेषण आवश्यक है। गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे (डुप्लीकेट) मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। अनुपस्थित की श्रेणी में उन मतदाताओं को रखा गया है जो गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को मिले ही नहीं। इनमें स्थानांतरित और दोहरे मतदाता भी शामिल हो सकते हैं। स्थानांतरित मतदाताओं में उनको शामिल किया गया है जो अपना निवास स्थान छोड़ कर कहीं और चले गए हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम भी मसौदा सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा जिन मतदाताओं के एक से अधिक स्थान पर वोट थे उनके नाम भी इस सूची से हटाए जा चुके हैं। इसके बाद एक बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जिनके नाम साल 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज है लेकिन गहन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है और न ही उनके माता, पिता, दादी या दादा का नाम उसमें मिला है। ऐसे मतदाताओं के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए देश के 12 राज्यों में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। मसौदा सूची जारी होने के बाद 20 प्रतिशत तक मतदाताओं के वोट कटने की संभावना से राजनैतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों की नींद उड़ी हुई है। सभी राज्यों में पार्टी के बड़े नेता लगातार अपने बूथ स्तर के कार्यकताओं को इसके लिए चेता रहे हैं और पार्टी समर्थकों के वोट न कटने देने के लिए प्रयास करने को कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बीते दिनों जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर चेतावनी दी थी कि जिन मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत भाजपा के समर्थक हैं। इतना ही नहीं एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात आदि राज्यों में भी भारी हलचल है। मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का राजनैतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका आकलन करने से पहले इस अभियान के तहत हटाए जाने वाले मतदाताओं का विश्लेषण आवश्यक है। गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे (डुप्लीकेट) मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। अनुपस्थित की श्रेणी में उन मतदाताओं को रखा गया है जो गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को मिले ही नहीं। इनमें स्थानांतरित और दोहरे मतदाता भी शामिल हो सकते हैं। स्थानांतरित मतदाताओं में उनको शामिल किया गया है जो अपना निवास स्थान छोड़ कर कहीं और चले गए हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम भी मसौदा सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा जिन मतदाताओं के एक से अधिक स्थान पर वोट थे उनके नाम भी इस सूची से हटाए जा चुके हैं। इसके बाद एक बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जिनके नाम साल 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज है लेकिन गहन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है और न ही उनके माता, पिता, दादी या दादा का नाम उसमें मिला है। ऐसे मतदाताओं के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्हें अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। लेकिन, सबसे बड़ी चिंता की बात पश्चिम बंगाल में मिले लगभग एक करोड़ 36 लाख तार्किक विसंगतियों वाले संदिग्ध मतदाताओं को लेकर है। इन मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना प्रपत्रों में जिस प्रकार की विसंगतियां मिली हैं, उन पर सहज रूप से विश्वास करना मुश्किल है। अनेक मतदाताओं की आयु और उनके माता-पिता की आयु में दस वर्ष या दादा-दादी की आयु से 40 वर्ष से कम का अंतर है। चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रकार के मतदाताओं की विशेष जांच की तैयारी की जा रही है। मतदाता सूचियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रथम चरण पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम अन्तिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इस आंकड़े के सामने आने के बाद विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी भाजपा के नेताओं के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में भाजपा की सीटें इकाई के अंकों में सिमट कर रह जाएंगी तो भाजपा के नेता सपा नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि अवैध मतदाताओं के वोट कटने से वे बौखलाए हुए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी 58.20 लाख मतदाताओं के नाम कटने के अलावा एक करोड़ 67 लाख मतदाताओं का नाम अंतिम सूची में शामिल करने से पहले गहन परीक्षण किया जा रहा है, जिसने ममता दीदी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तो इस प्रक्रिया को रुकवाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गई हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के बाद सबसे ज्यादा हलचल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है। राजनैतिक दलों के नेताओं के अलावा बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग भी इस पर दिमागी कसरत करता दिख रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 50 हजार वोट कटने का चुनावी नतीजों पर क्या असर होगा, जबकि अधिकतर सीटों पर जीत हार का अंतर 20 हजार से कम रहता है। पिछले विधानसभा चुनावों में तो 49 सीटों पर जीत हार का अंतर पांच हजार से भी कम था। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि सबसे ज्यादा मतदाता शहरी क्षेत्रों से कटे हैं। चूंकि शहरी क्षेत्र में भाजपा को अधिक प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। लेकिन, इसका दूसरा पहलू भी है, शहरी क्षेत्र से जिन मतदाताओं के वोट कटे हैं उनमें से अधिकतर के गांव में वोट थे, जो पंचायत चुनाव में तो गांव जाकर वोट देते थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शहरों में ही मतदान करते थे। ऐसे में अगर ये मतदाता अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी गांव जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो वे ग्रामीण सीटों पर इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। जिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं के नामों को हटाया गया है, उनका लाभ सिर्फ उन राजनैतिक दलों को मिलता था, जो फर्जी मतदान करा पाते थे। इन नामों के कटने का नुकसान चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात राज्यों में तो सत्ताधारी दल को हो सकता है, लेकिन उप्र में इसका कोई खास प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इससे मतदान प्रतिशत के आंकड़े बेहतर दिखेंगे, जिसका लाभ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगा। गैर भाजपा विपक्षी को सबसे ज्यादा चिंता पिछले विशेष पुनरीक्षण अभियान 2003 से मेल न होने के कारण हटाए गए मतदाताओं को लेकर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या एक करोड़ चार लाख है और पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 31 लाख है। मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में रह रहे अवैध घुसपैठियों हड़कम्प मच गया। संभावित कार्रवाई के डर से इन अवैध घुसपैठियों की रातों रात पूरी-पूरी बस्तियां उजड़ गईं। अपने देश वापस लौटने के लिए बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठियों की भीड़ को खबरिया टीवी चैनलों पर खूब दिखाया गया। अवैध तरीके से दशकों से भारत में रह रहे ये लोग बताते दिखाई दिए कि किस तरह उनको यहां का मतदाता भी बना दिया गया और उन्होंने चुनावों के दौरान वोट भी डाले। पश्चिम बंगाल के एक करोड़ 36 लाख तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इन मतदाताओं के बारे में माना जाता है कि ये गैर भाजपा दलों के प्रतिबद्ध मतदाता थे। इनके वोट कटने से विपक्षी दल सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इसीलिए मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के इस अभियान को इनके नेता एसआईआर की आड़ में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) बता रहे हैं।

गीता का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

भगवान श्रीकृष्ण का भगवद गीता के रूप में अर्जुन को दिया गया शाश्वत उपदेश का आज विश्व भर में प्रसार हो चुका है। आज यह विश्व के सर्वाधिक सम्मानित आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। इसी प्रकार, कुरुक्षेत्र स्थित पावन ब्रह्म सरोवर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव भी एक क्षेत्रीय आयोजन न रह कर, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन बन चुका है, जो हर महाद्वीप में गीता के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। आध्यात्मिक चेतना जगाने वाले गीता महोत्सव का आयोजन, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1989 में शुरू किया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता का संदेश समूचे विश्व में पहुंचाने के उद्देश्य से इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का रूप दिए जाने की इच्छा व्यक्त की। इसी के अनुरूप हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जिसका उद्देश्य गीता का शांति, सद?्भाव और सार्वभौमिक बंधुत्व का शाश्वत सन्देश सम्पूर्ण मानवता तक पहुंचाना था। गीता के संदेश ने विश्व भर में जो गूंज पैदा की, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित विश्व के 30 से अधिक देशों में किया जा चुका है। यह महोत्सव धीरे-धीरे एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व के देश शामिल हो रहे हैं। गीता की वैश्विक यात्रा में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सऊदी अरब में आयोजित महोत्सव रहा है। महोत्सव के अंतर्गत गीता को ओटावा में कनाडा की संसद, लंदन के हाउस ऑफ कॉमंस तथा अन्य देशों के इसी प्रकार के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों में रखा गया। इतना ही नहीं, ब्रैम्पटन (कनाडा) और लेस्टर (यूके) शहरों ने अपने एक नगर उद्यान का नाम श्रीमद?्भगवद् गीता पार्क रखा है, तथा विश्व के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में गीता पीठ भी स्थापित की गई है। वर्ष 2025 में विदेश मंत्रालय एक प्रमुख साझेदार के रूप में आगे आया और इसने महोत्सव को व्यापक सहयोग दिया। विश्वभर में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करके विदेश मंत्रालय ने महोत्सव को और सशक्त किया, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता आसान की तथा गीता को शांति व सद?्भाव के सार्वभौमिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करके भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को नई ऊंचाई दी। वास्तव में, महोत्सव का वैश्विक स्वरूप बनने से बहुत पहले ही अनेक विदेशी विद्वान और दार्शनिक, गीता का सन्देश गहराई से समझ कर इसकी सराहना कर चुके थे। वेदों और उपनिषदों का लैटिन में अनुवाद करने वाले जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर, गीता में निहित सर्वोच्च ज्ञान को अत्यंत मूल्यवान मानते थे। एक अन्य जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर गीता से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इसकी शिक्षाओं में वैराग्य के माध्यम से मुक्ति का मार्ग पाया था। उन्होंने इसे विश्व के पास प्रदर्शित करने योग्य सबसे गहन और सर्वोच्च वस्तु बताया और भौतिक जगत को क्षणभंगुर एवं माया बताने वाली इसकी विवेचना में गहरा साम्य पाया। वे गीता से इतने अधिक अभिभूत थे कि इसे एक उदात्त दार्शनिक गीत, गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्राचीन ज्ञान का सशक्त साक्षी मानते हुए गीता को सिर पर रखकर बर्लिन की गलियों में दौड़े थे। अपने बहुप्रशंसित मन की बात कार्यक्रम के नवंबर 2025 के अंक में प्रधानमंत्री ने भगवद् गीता की वैश्विक अनुगूंज रेखांकित की। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में विश्वभर से प्रतिभागियों के सम्मिलित होने का उल्लेख किया। उन्होंने सऊदी अरब, लात्विया तथा अन्य देशों में हाल में हुए आयोजनों का उल्लेख करते हुए बताया कि अनेक देश गीता के शांति और करुणा के संदेश से प्रेरणा पा रहे हैं।प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना मेरे लिए विशेष रहा। मैं यह देख कर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने वाले इस महोत्सव की प्रमुख विशेषताओं में आरती एवं दीपोत्सव, गीता यज्ञ और गीता पाठ, गीता का वैश्विक सामूहिक उच्चार (साल 2025 में 21,000 विद्यार्थियों सहित 1,00,000 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया), गीता सद?्भावना यात्रा, पुस्तक, शिल्प एवं खाद्य मेले, रन फॉर गीता तथा गीता क्विज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सर्वधर्म संत सम्मेलन का आयोजन भी होता है जिसमें विभिन्न धर्मों तथा विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों से आए विद्वान, गीता की महिमा का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि वर्तमान अशांत एवं संघर्षरत विश्व में, गीता का सन्देश कैसे मानवता के लिए सहायक हो रहा है। यह तथ्य रेखांकित करता है कि गीता किसी एक धर्म की न होकर सम्पूर्ण मानवता की धरोहर है और कैसे यह दिव्य ग्रंथ सभी को एकजुट करने में भूमिका निभा सकता है। इस वर्ष महोत्सव को अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में विदेश मंत्रालय ने निर्णायक भूमिका निभाई और गीता सम्मेलन में 25 प्रतिष्ठित विदेशी विद्वानों की सहभागिता सुनिश्चित हुई। भगवद् गीता के संदेश का सर्वमान्य स्वरूप और सर्वव्यापकता इसे एक सार्वभौमिक ग्रंथ बनाती है। यह किसी एक धर्म से संदेश नहीं रखती। गीता, मानव को जीने की कला सिखाती है और कर्मयोग (निःस्वार्थ कर्म का मार्ग), भक्ति (समर्पण) तथा सांख्य (ज्ञान) जैसे इसके उपदेश विश्व भर के साधकों को आकर्षित करते हैं। यह निष्काम भाव से लाभ-हानि तथा जय-पराजय जैसी गणनाओं से ऊपर उठकर, कर्म करने का महान संदेश देती है। गीता में धर्म शब्द किसी संप्रदाय या धर्म विशेष का द्योतक नहीं है। यह तो कर्तव्य, नैतिक एवं आचारिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है, जो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मानवता की सेवा करता है। कई अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करने के लिए कुछ सजग और ठोस उपाय किए गए।

वर्षों से न्याय के इंतजार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के गत वर्ष के आंकड़ों की ही मानें तो देश के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ही 65 लाख से अधिक मुकदमे निर्णय के इंतजार में दशकों से प्रतीक्षारत हैं। 3 हजार से अधिक मामले तो 50 साल भी अधिक समय से लंबित हैं। 10 साल या इससे अधिक समय से निर्णय का इंतजार कर रहे मुकदमों की बात करें तो यह संख्या इतनी अधिक है कि सोचने पर मजबूर कर देती है। देश के 25 उच्च न्यायालयों व राज्यों के जिला अदालतों में लबित मुकदमों की बात की जाए तो यह सामने आ रहा है कि 54 लाख 58 हजार 832 मुकदमे 10 से 20 साल की अवधि के हैं और निष्पादन का इंतजार कर रहे हैं। 20 से 30 साल और 30 से 40 साल की अवधि के निर्णय के इंतजार के मुकदमे भी लाखों में हैं। सालों से लोक अदालतें भी लग रही हैं, पर मुकदमों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अदालतों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि नित नए सुधार और मुकदमों के अंबार से स्वयं अदालतों में बैठे माननीय न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत और सरकार चिंतित और गंभीर है। इसका हल खोजने के प्रयास जारी हैं। चिंता की बात यह है कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 50 साल से अधिक समय से आज भी 3442 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2329 मुकदमे उच्च न्यायालयों व 1113 मुकदमे जिला न्यायालयों में पेंडिंग हैं। मुकदमों की संख्या को लेकर सवाल नहीं है, क्योंकि यदि 50 साल से एक मुकदमा भी पेंडिंग है, तो यह अपने आप में गंभीर है। सवाल 50 साल की अवधि का विश्लेषण करने का भी है। 50 साल की अवधि का मतलब कई मामलों में तो निश्चित रुप से अदालतों में हाजिरी देते-देते दो से तीन पीढ़ियां खप गई होंगी। दोनों ही अदालतों में 50 साल से अधिक अवधि के लंबित मुकदमों में सिविल प्रकरण ही अधिक है। निश्चित रुप में इनमें से अधिकतर मामले जमीन जायदाद को लेकर होंगे। हालांकि दोनों अदालतों के मिलाकर 459 मुकदमें आपराधिक श्रेणी के हैं और 50 साल से अधिक समय से निर्णय के इंतजार में है। अब आज से 50 साल पहले जिसने भी जैसा भी अपराध किया था या जिसने भी जैसा भी अपराधी के कारण मानसिक-शारीरिक संताप या प्रताड़ना झेली थी, उनमें से कई तो हो सकता है दुनिया में न हों या उनकी शारीरिक-मानसिक हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इस समस्या पर गंभीर चिंतन किया जाता रहा है। इसके समाधान खोजने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। अच्छी बात है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के अधिकतर पद भरे रहने लगे हैं। समग्र प्रयासों से उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के न्यायमूर्तियों के पद भी भरने के प्रति गंभीर प्रयास जारी हैं, पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि एक मोटे अनुमान के अनुसर उच्च न्यायालयों के करीब 1100 से अधिक स्वीकृत पदों में से 300-350 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। जहां तक जिला अदालतों का प्रश्न है, एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 4 से 5 हजार पद रिक्त हैं। इसमें दो राय नहीं कि इससे काम प्रभावित होता है। दस साल से अधिक के कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक मुकदमों में निर्णय का इंतजार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था पर प्रश्न तो उठाता ही है। इसी तरह से निस्तारण में देरी के लिए किसी पर दोष जड़ने से भी कोई समाधान नहीं होने वाला है। यह कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह का सिस्टम विकसित करना होगा जिससे पुराने मुकदमों को प्राथमिकता से निपटाया जा सके। सरकार ने कुछ माह पहले कानून में संशोधन कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उससे निस्तारण की समय-सीमा तय होगी। कुछ इस तरह का रोस्टर सिस्टम या केवल और केवल पुराने मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से ही माननीय न्यायाधीशों की बेंच बना दी जाएं, तो प्राथमिकता से वर्षों से न्याय की आस में चल रहे मुकदमों का निष्पादन हो सके।

ट्रंप की जल्दबाजी

रूस पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को कांग्रेस से पारित कराने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी को आधिकारिक तौर पर रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के एक दंडात्मक उपाय के के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह विधेयक ट्रंप को मॉस्को से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसद तक शुल्क (टैरिफ) लगाने की शक्ति देता है। फिर भी, यह विधायी कदम 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद उठाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद की अपनी तमाम प्रेस वाताओं के दौरान, ट्रम्प ने अमेरिका के मुख्य रणनीतिक हित के तौर पर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर जोर दिया। रूसी प्रतिबंधों और वेनेजुएला के तेल परिसंपतियों पर यह दोहरा जोर बताता है कि इन दोनों कदमों का रिश्ता भू-राजनैतिक सजा देने से कम और ऐसे वक्त में पेट्रोडॉलर के दबदबे को बचाने से ज्यादा है, जब उसका वर्चस्व कम हो रहा है। दशकों से,श तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय की जाती रही है और ज्यादातर लेन-देन भी उसी में होता रहा है। उस व्यवस्था ने 20वीं सदी के ज्यादातर वक्त तक वैश्विक वित्त में डॉलर की अहमियत को बनाए रखा। लेकिन, 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों और 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद इन प्रतिबंधों को और सख्त किए जाने के बाद, चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ताओं ने ऐसी व्यापारिक व्यवस्था को मजबूत किया है, जो डॉलर की अनदेखी करते हैं। मसलन भारत ने 2022 से बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल का आयात किया है, जो युद्ध के दौर में रूस के कच्चे तेल के निर्यात का 20 फीसद से ज्यादा हिस्सा है। चीन की खरीदारी और भी ज्यादा रही, जो छूट पर ऊर्जा हासिल करने और गैर-डॉलर निपटान तंत्र को आजमाने की उसकी रणनीति को दशार्ती है। ऊर्जा व्यापार में युआन के इस्तेमाल से रेनमिनबी (चीन की आधिकारिक मुद्रा) के अंतरराष्ट्रीयकरण में काफी इजाफा हुआ है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Green outcomes from the red budget folder

Time was when November was one of the most pleasant months in Delhi, with just the whiff of winter in a city of extreme weathers. Not anymore. Foul air has replaced the aroma of roasted peanuts and chhole bhature as conversation starters in the national capital. Citizens have traded their old Celcius talk for a new set of numbers to moan about. Today, the air quality index regularly announced on TV triggers sighs and protests.

Environmental issues have clearly hit India's political mainstream. Public protests erupted not only on the AQI that reached hazardous levels, but also on a new height-based definition of the Aravalli hills, sparking fears of illegal mining and environmental harm and forcing the government to backtrack despite a qualified Supreme Court sanction. A furore over water contamination deaths in Indore, showcased as India's cleanest municipal zone, followed.

The environment ministry faced howls as the new year dawned after it amended guidelines to allow forest zones to have commercial plantations by private entities. The death of environment crusader Madhav Gadgil rang a sombre note on the importance of sustainability.As Finance Minister Nirmala Sitharaman meets various interest groups to craft her annual budget for the new financial year, it is time to ask if environmental outcomes should be highlighted in the budgetary numbers so that we can take note of what the government is doing (or not) for sustainability in the world's most populous and fastest-growing economy.Green budgeting' is unheard of in India despite decades of avowed political commitment to environmental issues. It tracks fiscal revenues and expenditure allocations by focusing on schemes and measures that affect the environment and sustainability. For starters, it is a sound way to measure public commitment to environmental goals. The Organisation for Economic Cooperation and Development has been promoting green budgeting since 2017, when it launched the Paris Collaborative at its One Planet Summit.

Historically, progressive economists in India have been monitoring health, education and gender issues addressed and outlays allocated as part of their toothcombing of budgetary measures. Such a focused analysis is much needed. But such an effort can invite trouble. The prestigious Delhi School of Economics courted controversy a few weeks ago as the Delhi University's academic panel objected to its syllabus on 'Economics of Gender' that covered some historical and ideological issues.Green budgeting may face similar pitfalls. But there has to be a beginning. Nearly 80 years after independence, India has seen two long spells of economic vision covering roughly 40 years each. The first four decades were a lot about socialist planning and government control, while the following years have seen an obsession with macroeconomic stability and its attendant points: inflation, interest rates and GDP growth. Both these worldviews have unconsciously sidestepped the environmental side effects of growth.We are now looking at a scenario in which one kind of positive numbers results in an unfocused set of negative ones. An agricultural boom in some areas leads to the hazardous burning of stubble. Automobiles driven by a growing middle class result in traffic jams. Mountains of unregulated plastic and other waste pollute the air and water of our cities. The data centres powering the artificial intelligence boom currently under way will also leave a massive environmental footprint because of its humongous energy needs.

Modi govt's cultural ambition

THE GREAT GAME: The RSS and the BJP are keen to carve out a special memory in the heart of India

INDIA may be in the throes of a political spat with its most important foreign partner, the US, while the economy, as noted financial journalist TN Ninan pointed out in these columns earlier this week, is more shy than sociable — but the government's never-say-die ambition to scale the high cultural heights remains. The first gallery of what's expected to be the world's largest museum, the Yuge Yugeen Bharat, will open by the end of the year.The scale is certainly formidable. As many as 100,000 artefacts telling the story of India, from the Indus Valley civilisation to the present day, will be showcased across 30 galleries in the North Block and South Block, British Raj buildings that have housed the bureaucratic elite in the heart of Lutyens' Delhi over the last hundred years.

There's something about a museum that appeals to the Modi government. Perhaps, like the Bahujan Samaj Party's Dalit leader Mayawati — whose monuments to herself and her mentors, Kanshi Ram and Babasaheb Ambedkar, are littered around Lucknow and the outskirts of Delhi — Modi understands that you may hate them or love them, but monuments are always going to stand the test of time. (That's why statues of Lenin and Marx were first attacked by counter-revolutionaries when it was clear the Soviet Union was falling in end-1991.) And that's why, New Delhi has been slowly rebuilt and reshaped in the last 11 years since Modi became PM.From the Pradhan Mantri Sangrahalaya, or the Prime Ministers' Museum, where there are galleries to every PM, including Modi — which gets a mention on the public address system of the Shatabdi trains coming into Delhi — to Yuge Yugeen Bharat, the demonstration of the RSS and BJP's ambition to carve out a special memory in the heart of India is unparalleled.

The impressive fact is that nothing is too small for the BJP. At the Harivallabh music festival in Jalandhar which celebrated its 150th anniversary in the last week of December, Culture Minister Gajendra Shekhawat was unable to show up — so he sent a video message saying the government would be happy to build an auditorium for India's oldest music festival. The unspoken message that accompanied the loud claps to the video message was that the BJP would do anything to help Punjab recover its diminished heritage — and that it would certainly help if the people of Punjab were to return the favour, by voting them in.That's why it was surprising to see the scarce attention to detail at the exhibition showcasing the Piprahwa Buddha relics recently inaugurated by the PM in Delhi. For those who came late to the story, five small caskets containing jewel stones, bone fragments and ashes of Gautam Buddha were discovered in 1898 by William Claxton Peppe, a British colonial engineer who managed several estates south of the Nepal border, including the Birdpur Estate in a village called Piprahwa. Fast-forward to 2025, when the Peppe descendants decided to auction the Buddha relics in their keep in Hong Kong, leading to a nationwide furore, which in turn pushed the Centre to partner with the Godrej Industries Group to buy the jewel relics and bring them back to the motherland.

"It would make every Indian proud that the sacred Piprahwa relics of Bhagwan Buddha have come home

(to India) after 127 long years…" the PM said at the time. Certainly, the ambition to position India as the rightful inheritor of one ancient civilisation, the Indus Valley, and one ancient school of thought, Buddhism, is striking to see.There they are, the magnificent jewels, in a bulletproof case in front of you. Gaze, then, upon the "stars in silver and gold, discs of gold leaf embossed with Buddhist symbols, and numerous pearls of many sizes…drilled beads, stars and flowers cut from red or white cornelian, amethyst, topaz, garnet, coral and crystal" — all this information gleaned from www.piprahwa.com, because it isn't available at the exhibition, neither regurgitated by the young, blissfully ignorant volunteers present nor offered by Design Factory India (DFI), the company that has put together the show. It may be mentioned here that the DFI's claim to fame is that it has built a museum in Vadnagar on the town's Buddhist connection as well as one in Bhuj, memorialising the 2001 earthquake.

The exhibition also contains stunning sculptures manifesting the Buddha, sourced from collections in the Indian Museum in Kolkata, the National Museum in Delhi and museums elsewhere in the country. Many of these sculptures once came from parts of Khyber-Pakhtunkhwa, now in Pakistan, except the word "Pakistan" on the placard has been replaced by "Undivided India." Some paintings have been "recreated" — meaning, they were in such poor shape in the museum in which they were kept that it was not possible to relocate them.Look closely now at the thousand-year-old sculptures. You know they've been cleaned — they have that shiny, polished look, stripped of the accumulated decades of dust and grime. The DFI confirms your hypothesis. You hope the cleaners used good cleaning liquid that does not eat schist — it would be good to know what the process was.

This public-private partnership between Godrej Industries and the government is clearly a model for the future. It's not clear, though, whether the Godrej folks have donated the jewel relics to the country or the government has bought them off. Whatever it is, they are home.

And so, as the Yuge Yugeen Bharat museum takes shape in the heart of Delhi, a stone's throw away from the PM's new home that is being completed, cast your eyes to Ayodhya, where a museum of Indian temple architecture is being built in the shadow of the Ram Mandir. This is an out-and-out private partnership, but it's also clear that the government is watching closely. The outstanding design is a brainchild of the Zaha Hadid architectural concern — which lost the contract to build Yuge Yugeen to Debasish Guha's Arcop consortium and the Los Angeles-based Kulapat Yantrasast — while the funding is being provided by a Tatas' subsidiary called Ecofirst.

But you are now back home in Chandigarh and so another visit to the Government Museum in Sector 10, which also houses the Buddha Gandhara sculptures — split half-half with the Lahore Museum when India became independent — is essential, if only to see if the spirit of change has travelled to this part of the country. You still inscribe your name in a register, just like if you were visiting an important bureaucrat at the Secretariat — just the museum ticket is not enough. The museum is still desolate. Some exhibits in the miniature gallery have been moved because the roof is being repaired, but work has come to a standstill because funds, seemingly, have run out.

Maha success: BJP-led Mahayuti shines in local body polls

The Tribune Editorial: The BJP has overwhelmingly eclipsed not only its rivals but also its allies in the BMC polls.

JUST over a year after the BJP-led Mahayuti routed the Opposition in the Maharashtra Assembly elections, the ruling alliance has asserted its dominance in the statewide local body polls as well. The BJP has emerged as the single largest party in the high-stakes Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) polls. The outcome marks a decisive shift in Mumbai's pecking order; as an undivided party, the Bal Thackeray-founded Shiv Sena ruled India's financial capital for decades. Now, the Sena faction led by Deputy CM Eknath Shinde will play second fiddle to the saffron party in the BMC, as is the case in the state government. Even the reunion of the Thackeray cousins after two decades failed to stop the BJP juggernaut. Former CM Uddhav Thackeray's Shiv Sena and Raj Thackeray's Maharashtra Navnirman Sena found it very hard to translate symbolic unity into electoral success. The desperate alliance between the Nationalist Congress Party factions led by Sharad Pawar and his nephew Ajit Pawar

came a cropper in Pune.The BMC matters enormously as it is India's richest civic body; its budget for 2025-26 is a whopping Rs 74,427 crore, higher even than that of states such as Himachal Pradesh and Goa. The local body's new composition will have far-reaching implications for Mumbai's governance, policy priorities and the political dynamics in Maharashtra. The poll verdict is an endorsement of Chief Minister Devendra Fadnavis' mega development pitch, even as the Thackerays' "Marathi manoos" card did not find many voters. The Congress, too, was relegated to the sidelines in the big battles, but it did cause a flutter with its allegation that the "indelible" ink used in the polls could be easily erased.The results have put a question mark over the future of the Opposition's Maha Vikas Aghadi alliance, with its constituents struggling to stay relevant. Maharashtra's most prominent political families — the Thackerays and the Pawars — are now a pale shadow of their former selves.

The BJP has overwhelmingly eclipsed not only its rivals but also its allies.

China's renewed interest in Shaksgam valley

The abrupt attention directed towards the Shaksgam valley coincides with a Chinese delegation's meeting with the BJP and RSS in Delhi.

The Indian media recently observed the swift development of China's road network in the Shaksgam valley, which is backed by numerous construction sites, utilising Landsat satellite data from the global land imaging body USGS EROS Center.The abrupt attention directed towards the Shaksgam valley coincides unexpectedly with the Chinese Communist Party delegation's meeting with the BJP and RSS in New Delhi. Such underhand manoeuvres are not new, having taken place multiple times alongside major occurrences. This represents a shrewd strategy utilised by a group that persistently attempts to hinder a positive normalisation process. Consequently, this is the reason India lacks trustChinese construction endeavours in Shaksgam are not a recent phenomenon. The People's Liberation Army has been monitoring the Shaksgam valley in West Karakoram since its influence expanded in Depsang (East Karakoram) in 2013.India was undoubtedly not informed regarding the development of a new road in the Shaksgam valley trijunction. The past satellite imagery has shown that China's activities in this area began immediately after the 2017 Doklam tri-junction standoff.Since 2018, China has improved its connectivity to the Aghil Pass. Open-source intelligence satellite images have revealed that China has built a 70-km road in the Aghil Pass area.

China's main objective regarding Shaksgam has been to shorten the travel from Kashgar to Skardu and Hunza via the G-219 highway, which traverses the Karakoram and the Aghil Pass. The present road is part of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

In 1963, Pakistan formally ceded over 5,400 sq km of the Shaksgam region through a boundary agreement. However, the actual territories transferred to China encompassed the entire Karakoram-Tract, totaling 20,000 sq km in return for approximately 750 sq km.

However, according to Article VI of the 1963 Sino-Pak Boundary Agreement, it is stipulated that "The two parties agreed that after the resolution of the Kashmir dispute between Pakistan and India, the relevant sovereign authority will reopen negotiations with the Chinese government regarding the boundary as outlined in Article Two of the current Agreement, to sign a formal Boundary Treaty to replace the existing agreement." Since 1963, China has regarded the Shaksgam-Karakoram tract as provisional, with sovereignty subject to renegotiation, which should ultimately be resolved between India and Pakistan.

India had the chance to resolve the issue during the conflict in 1972; however, the Simla Agreement signed afterward left the disputes regarding the Siachen Glacier and the Karakoram Tract unresolved. The Simla Treaty did not clarify the final 100 km of the ceasefire line that runs from the end of the Line of Control to the border with China.A decisive military operation in 1972 could have enabled India to reclaim not only the entire Siachen Glacier but also 5,400 sq km of Indian territory in Shaksgam and Karakoram Tract.

The second opportunity for India to address the issue arose after the 1999 Kargil war.The theoretical trijunction point of India, Pakistan, and China is presently situated near Indira Col, extending from Sia Kangri Point 7422 to Point 6599, covering a distance of 59 km, where the Actual Ground Position Line (AGPL) between Indian and Pakistani forces intersects with the Chinese border.From NJ 9842, the AGPL delimitation line follows the Saltoro Ridge, which is under Indian control, although Pakistan disputes this and aims to extend the delimitation line eastward from NJ 9842 to connect with the Karakoram Pass.At present, 75 percent of the territory of India that was transferred by Pakistan to China is incorporated into the Tashkurgan Tajik Autonomous County in Xinjiang, while the remaining 25 percent is situated in Yarkand Yecheng (Kargilik) County.China continues to refer to the Indian Consulate building at Chini Bagh as the Pakistan-India Consulate. Since then, China has been actively engaged in the

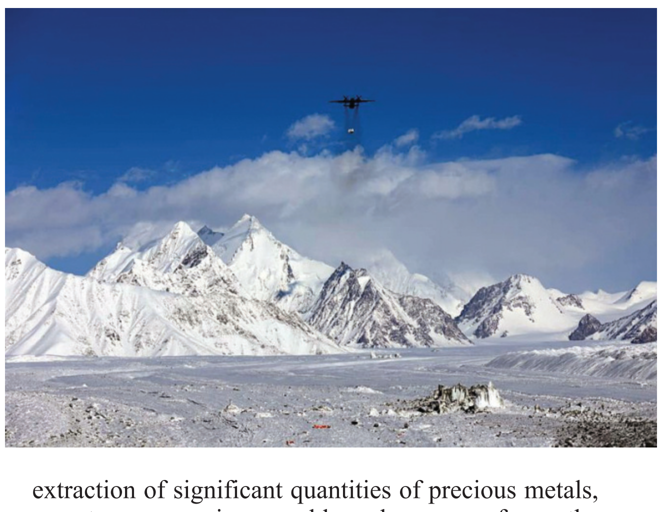

extraction of significant quantities of precious metals, gemstones, uranium, gold and copper from the Shaksgam Valley.India has persistently expressed its formal objections to both Chinese and Pakistani officials concerning illegal efforts to change the status quo at the Daulat Beg Oldie-Karakoram Pass. The decision not to open the Karakoram Pass for trade has proven to be a poor strategy, even though the region is not contested and is regarded as an Internal Boundary (IB), rather than the Line of Actual Control (LAC).

The conflict has emerged in recent years as the PLA endeavours to construct a second road through the southern Karakoram range providing the PLA with access to the trijunction point near Siachen.Former Army Chief General Bipin Rawat then dismissed allegations of any Chinese construction in the Shaksgam Valley, claiming that such an endeavour is nearly "impossible" and therefore "not a threat."

It is also accurate to state that the Indian authorities have been overly preoccupied with perceived threats from the Tibetan front, neglecting the significance of the Eastern Karakoram sector.Nonetheless, the strategic placement of the road along the Teram Sher axis could have profound operational consequences for India in the Siachen, Karakoram Pass, Daulat Beg Oldie, and Depsang regions, potentially escalating tensions with Pakistan.Pakistani military forces, which previously did not have direct access to the Teram Shehr glacier, may now be positioned to cooperate with the Chinese at the trijunction, thereby posing a threat to Indian supply routes to the Siachen Glacier.One possible approach for India might entail military intervention to secure the Teram Shehr glacier. Nevertheless, such a course of action could escalate into a three-front conflict, leading China to initiate additional confrontations in eastern Ladakh.

Over the years, India has significantly enhanced its infrastructure in the Karakoram region. Another alternative for the Indian military is to push beyond the Turtuk Sector to seize the Chorbat Lungpa Valley across the Shyok River and gain control over adjoining villages. This offers a distinctive opportunity to acquire land in Gilgit-Baltistan with minimal demographic impact.

Sensex, Nifty Open Sharply Lower Amid Weak Global Cues, Rising Global Trade Tensions

New Delhi.(Agency)

The Indian benchmark indices opened the week in the red zone on Monday, tracking weak global cues after geopolitical trade tensions rose due to US administration's comments of additional tariffs on European countries.

As of 9.30 am, Sensex lost 449 points, or 0.54 per cent to reach 83,120 and Nifty declined 148 points, or 0.58 per cent to 25,546.Main broadcap indices performed in line with benchmark indices, with the Nifty Midcap 100 losing 0.42 per cent, and the Nifty Smallcap 100 easing 0.54 per cent.Among sectors, except Nifty FMCG, all indices were trading in the red. IT, media as well as oil and gas were among major losers, down over 1 per cent each.

Immediate support lies at 25,600 and 25,450 zones, while resistance remained at 25,875 followed by 26,000 and 26,100, market watchers said.

Analysts predicted volatile days for stock markets in the near-term amid heightened geopolitical risks. They highlighted US President Donald Trump's disruptive policies impacting international trade and global economic growth."If President Trump walks his talk and imposes 10 per cent tariffs on the eight European countries on February 1st and follows it up by raising the tariffs to 25 per cent from June 1 onwards, retaliation by the European bloc is almost certain," they said.Asia-Pacific markets traded largely with losses during the morning session as investors parsed key economic data from China along with US President Donald Trump's threats to European countries on additional tariffs for gaining control over Greenland.China's economic growth slowed to its weakest pace in nearly three years in the fourth quarter amid decline in domestic demand.

In Asian markets, China's Shanghai index added 0.13 per cent, and Shenzhen eased 0.01 per cent, Japan's Nikkei declined 1.05 per cent, while Hong Kong's Hang Seng Index lost 1 per cent. South Korea's Kospi advanced 0.85 per cent.The US markets ended in the red in the last trading session as Nasdaq eased 0.06 per cent. The S&P 500 lost 0.06 per cent, and the Dow declined 0.17 per cent.

On January 16, foreign institutional investors (FIIs) sold net equities worth Rs 4,346 crore, while domestic institutional investors (DIIs) were net buyers of equities worth Rs 3,935 crore.

IT union NITES files complaint with Labour Ministry against Wipro over delayed onboarding, hiring

CHENNAI.(Agency)

Pune-based IT and ITES union Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) on Monday said it has filed a complaint with the Union Labour Ministry against Wipro Limited over an alleged delay in onboarding fresh graduates and misleading recruitment practices. The union has sought intervention from Minister Mansukh Mandaviya.

NITES President Adv. Harpreet Singh Saluja said, "The affected candidates are fresh graduates selected through campus and off-campus recruitment processes conducted by Wipro Limited, including its Turbo and NextGen Talent hiring programs. Letters of Intent were issued to these candidates around May 2025, confirming their selection and detailing the role, compensation structure and onboarding process. In several cases, the company also issued formal onboarding communications confirming a joining date, work location and completion of documentation formalities."

Recently, Wipro, in a quarterly result announcement, had said that it is planning to recruit fresh graduates for specialised roles.He further said, "Over a period of several months, the affected candidates repeatedly approached the company through official emails, calls and written representations seeking clarity regarding their onboarding status. In response, they either received no reply or were provided vague and automated responses referring to business demand, future batches or tentative timelines that were never honoured. No written explanation, confirmed onboarding date or formal cancellation has been issued to date."He added that over 250 affected candidates from multiple states have approached NITES. NITES is prepared to submit all supporting documents, including Letters of Intent, onboarding communications, background verification records and correspondence exchanged with the company for the Ministry's consideration, it said in the letter.

Suzlon appoints Paulo Fernando Soares as President of Europe business

New Delhi.(Agency)

Home-grown renewable energy solutions provider Suzlon Group on Monday said it has appointed Paulo Fernando Soares as President of its Europe business to accelerate growth in the region.

Soares joins the company after a short stint at Sany Renewables in Europe, where he was serving as Managing Director, Suzlon said in a statement.

The company said it is strengthening its global leadership structure to drive the next phase of international growth under its Suzlon 2.0 strategy.

With four decades of experience in the wind industry, Soares will lead Suzlon's European operations with a mandate to develop regional capabilities, forge strategic partnerships, strengthen customer engagement, and drive market access across Europe.His track record includes leadership roles in business development, sales, and operations, it said.

Soares' role will also encompass building a robust organisational framework to ensure long-term success across European markets, the statement said, adding that he has served Suzlon previously as well for 5 years, playing a key role in setting up its Asian operations.

Shadowfax Technologies IPO opens today: Check price, GMP and other details

Shadowfax Technologies is set to enter the primary market tomorrow with its much-watched IPO. The issue comes at a time when online shopping and same-day delivery services are seeing steady growth across India.

New Delhi.(Agency)

Shadowfax Technologies Ltd, a well-known name in India's fast-growing logistics space, is set to open its initial public offering (IPO) tomorrow, January 20, 2026. The issue has already drawn attention due to the company's strong presence in e-commerce and quick commerce deliveries.

SIZE AND STRUCTURE OF THE IPO

The Shadowfax Technologies IPO is a book-built issue worth Rs 1,907.27 crore. It includes a fresh issue of shares worth Rs 1,000 crore and an offer for sale of Rs 907.27 crore by existing shareholders.While the fresh issue will help the company raise funds for its business needs, the offer for sale will allow current investors to partially exit their holdings.

IMPORTANT DATES TO TRACK

The IPO will open for subscription on January 20, 2026, and close on January 22, 2026. The basis of allotment is expected to be finalised on January 23, while the company is likely to make its stock market debut on January 28, 2026, on both the BSE and NSE.

PRICE BAND AND INVESTMENT DETAILS

Shadowfax Technologies has fixed the IPO price band at Rs 118 to Rs 124 per share. The lot size for investors is 120 shares, which means retail investors need to invest a minimum of Rs 14,880 at the upper end of the price band.For non-institutional investors, the minimum investment is higher. Small NIIs need to apply for 14 lots, while big NIIs must apply for 68 lots, translating into investments running into a few lakhs and over ten lakh rupees respectively.

ABOUT THE COMPANY

Founded in June 2016, Shadowfax Technologies Ltd is an Indian logistics solutions company focused on last-mile delivery. Over the years, it has built a strong presence in e-commerce and D2C parcel deliveries. The company also handles hyperlocal and quick commerce orders, offering same-day or even within-hours delivery in many locations.

In addition, Shadowfax provides SMS and personal courier services through its Flash app, catering to individual users and small businesses. Its wide service range has helped it become a key delivery partner for online platforms and brands.

GREY MARKET PREMIUM (GMP)

As of January 19, 2026, at 11:00 AM, the latest grey market premium (GMP) for the Shadowfax Technologies IPO stands at Rs 11 per share. Based on the upper price band of Rs 124, the estimated listing price works out to around Rs 135 per share.

This suggests a possible listing gain of 8.87%, though market observers caution that GMP figures are unofficial and can change quickly.

WHAT INVESTORS SHOULD KEEP IN MIND

Shadowfax operates in a competitive but fast-expanding logistics and quick commerce space. The rise of online shopping, same-day delivery, and D2C brands has increased demand for reliable delivery partners.

Bharat Coking Coal opens at 97% premium: Should you hold or sell BCCL shares

New Delhi.(Agency)

Shares of Bharat Coking Coal Limited (BCCL) made a strong start on their stock market debut, opening at a sharp premium to the IPO price.

BCCL stock listed at around a 97% gain over the issue price of Rs 23, reflecting the very high demand seen during the IPO phase. With such a strong opening, investors are now asking a key question: should they hold the stock or book profits?BCCL was the first mainboard IPO of 2026 and drew massive interest from all investor groups. The public issue was subscribed 143.85 times by the close of bidding.Retail investors subscribed the issue 49.37 times, the non-institutional investor category saw subscription of 240.49 times, and the qualified institutional buyer segment was subscribed 310.81 times, excluding anchor investors. The allotment was finalised on January 14, 2026, ahead of the listing.On listing day, the stock's opening was well above earlier grey market estimates, giving investors sharp gains right from the start. For those who received allotment, the listing translated into strong notional profits within minutes of the debut.

MARKET VIEW ON THE LISTING

Prashanth Tapse, Senior VP Research at

Mehta Equities Ltd, said BCCL was expected to list at a premium even before the debut. He noted that the stock was likely to list in the range of Rs 32 to Rs 35, implying a 39 to 52% premium over the issue price.According to him, the IPO saw exceptionally strong subscription across QIB, NII, and retail segments, which clearly reflected investor confidence.He said interest in the issue was driven by the scarcity value of the offering, as it gave investors a rare chance to gain exposure to India's largest and most integrated player in the coking coal value chain. Coking coal is a key input for the domestic steel industry, which added to the appeal.

Tapse said that from a valuation point of view, the issue was priced reasonably, especially for a low-ticket IPO. This helped create an attractive risk-reward balance for investors.He added that the company's dominant position in the coking coal segment and steady demand linked to ongoing steel capacity expansion support a positive medium-to-long-term outlook.

He also pointed out that structural demand trends in the steel sector could continue to support the business over time, making BCCL more than just a short-term listing play for some investors.

Silver Just About 4.2% Away From Crossing The Rs 3 Lakh Milestone

New Delhi.(Agency)

Silver prices have continued their remarkable rally, rising another 22 per cent in January so far, strengthening investor interest and keeping the white metal firmly in focus. The sharp surge has helped silver emerge as the top performer among major asset classes, supported by strong demand and multiple positive globalFrom the April close of Rs 95,917, silver has climbed nearly 200 per cent to settle at Rs 2,87,762 on Friday, a performance usually associated with multibagger stocks rather than commodities.Prices have also touched fresh record highs, with the latest peak of Rs 2,92,960 recorded last week.As silver surged past earlier expectations much faster than anticipated, analysts have been quick to revise their targets upward.Last year, domestic brokerages had projected silver prices at around Rs 1,10,000 by the end of the year, but those levels were crossed well before the midpoint.

The rally did not stop there, with prices going on to hit Rs 2,54,000, more than doubling earlier estimates.As these above-ground reserves shrink, holders of physical silver are demanding higher prices, further pushing rates upward.

At the beginning of 2025, silver was largely overlooked by investors, with few expecting it to

deliver such a sharp rally amid ongoing economic uncertainty and geopolitical tensions.Adding to the bullish sentiment is a shift in global central bank behaviour. After accumulating significant quantities of gold over the past three years, central banks are now reported to be adding silver to their reserves as well.This trend has provided additional support to prices, keeping MCX silver close to the Rs 3 lakh level.With the latest close of Rs 2,87,762, silver is now just about 4.2 per cent away from crossing the Rs 3 lakh milestone.

Could India-US Trade Deal Collapse US Senators Back Hard On India's Pulse Tariffs

Kolkata.(Agency)

Talks on the India-US trade agreement have once again hit a snag. Just as negotiators were nearing a breakthrough, two influential Republican senators urged US President Donald Trump to pressure India to remove tariffs on pulses.While the demand may seem small, it directly affects New Delhi's agricultural policies and its strategic push for self-reliance in pulses. Negotiators now face the risk that prior progress on the deal could be slowed or complicated.Senators Steve Daines of Montana and Kevin Cramer of North Dakota, representing America's largest pulse-producing states, called India's tariffs "unfair" and harmful to US farmers. They said that India is the world's largest consumer of pulses, accounting for roughly 27% of global demand.They argued that high tariffs prevent American producers from accessing this key market.Their main concern is India's 30% tax on yellow peas announced last October, which

took effect on November 1, 2025. The senators said such measures place US exporters at a disadvantage, even when their products are high-quality. They urged Trump to make pulses a priority in any future trade deal with India.The senators also recalled raising this issue during Trump's first term in 2020, when the letter they sent was directly delivered to Prime Minister Narendra Modi, helping US producers gain a seat at the negotiating table.

They wrote, "As America works to correct trade imbalances, US farmers are ready to help. They have the capacity to feed and fuel the world if trade opportunities are opened."Equal Tariffs For All Nations

While the senators called the tariffs discriminatory against the United States, India's pulse policy is broader. The government initially exempted yellow peas from tariffs until March 31, 2026.

Can Budget 2026 deliver scale, skills and digital growth for manufacturing

Budget 2026 is expected to play a key role in shaping the future of India's manufacturing sector. From expanding scale to building skilled manpower and driving digital adoption, the industry has clear expectations from the government.

New Delhi.(Agency)

As India moves closer to the Union Budget 2026–27, the manufacturing sector is firmly in focus. Industry experts say the coming year could be vital in shaping India's ambition to become a global manufacturing hub, with policy support, digital adoption and skill development emerging as key priorities.

MANUFACTURING GAINS MOMENTUM

India's manufacturing sector received a strong policy boost in FY 2025–26, helping it strengthen its role as a major driver of economic growth. Rajesh Mehra, Director and Promoter, Jaquar Group, says the shift in government approach has already started delivering results."India's manufacturing sector witnessed a decisive policy push in FY 2025–26, reinforcing its position as a central engine of economic growth," Mehra says. "The transition from the National Manufacturing Policy to the National Manufacturing Mission marked a clear shift from intent to execution."According to him, this move focused on ease of doing business, scalability and quality-led growth, while also strengthening the foundations of the Make in India programme. "This policy momentum resulted in expanding production hubs across India and helped move the country closer to a self-reliant manufacturing ecosystem," he adds.

BUDGET 2026 SEEN AS A KEY OPPORTUNITY

Looking ahead, Mehra believes manufacturing will play a central role in India's next phase of growth. "As we approach the Union Budget 2026–27, manufacturing stands firmly at the core of India's next growth phase, with the sector projected to contribute close to 25% of GDP by 2027," he says.He adds that the industry will closely track the government's continued focus on scale, quality and sustainability. "With manufacturing expected to reach the $1-

trillion milestone, sustained emphasis on reforms such as PLI schemes and Make in India will be critical to deepen domestic value addition, attract investments and create high-quality jobs," Mehra notes.

GLOBAL CHALLENGES REMAIN

Despite the positive momentum, experts caution that global uncertainties continue to pose challenges. Jitendra Nenavani, Assistant Professor –Operations, K J Somaiya Institute of Management, says geopolitical tensions and fluctuating raw material prices are adding pressure on manufacturers.India's manufacturing sector is facing a challenging global environment, marked by geopolitical uncertainty and volatility in the prices of key raw materials," Nenavani says. He adds that these factors could slow growth as the sector works towards long-term targets.

To meet its ambitions, Nenavani believes the sector must move beyond incremental changes. "There is a need to focus on strategic execution in two or three critical areas, while also sharpening the impact of existing initiatives such as PLI, Ease of Doing Business and Make in India," he explains.

DIGITAL PUSH AND SKILLED WORKFORCE IN FOCUS

Digitisation, especially for MSMEs, is one of the most urgent needs, according to Nenavani. "MSMEs form the backbone of India's manufacturing ecosystem," he says. "They must not only adopt advanced technologies but also build the capability to use digital tools such as artificial intelligence and blockchain."

Gigged, gagged: Delhi gig workers trapped in endless shifts, algorithmic control, vanishing rights

As platforms expand, gig workers fight a sorry state and unsafe conditions, while waiting for better days, reports Ifrah Mufti.

New Delhi.(Agency)

"There are nights when I just stand on the road till morning. No orders, no money. Just waiting," he said. It is 2.30 am.The road is eerily quiet with a flickering streetlight. Ali stands there braving the winter chills near Rajender Nagar, his phone clutched tightly in one hand, waiting for his Zomato app to show orders. It has been over an hour, but no luck.

The 24-year-old had come to Delhi six months ago to earn enough to help pay for his sister's wedding in Bihar and to fund the treatment of his elder brother, who has been unwell for over a year. Instead, most of what he earns disappears before it reaches home – lost to penalties, vehicle rent, and deductions he barely understands. Ali works from 6 pm to 9 am, a 15-hour shift that stretches across the city's most unsafe hours. When he first arrived in Delhi, he hoped to continue his bachelor's degree at Delhi University. Family emergencies forced him to abandon his studies.

Today, he rents a small room in the Jama Masjid area for Rs 2,500 per month and survives by stitching together two jobs: delivery rider at night and mobile technician during the day in Karol Bagh.

Amid growing protests by gig workers in Delhi, even as unions have written to the Labour Minister and approached the National Human Rights Commission (NHRC), alleging exploitative and coercive practices by app-based platforms, the reporter spoke to several gig workers in the capital to know that even when the 10-minute delivery enforcement has been revoked, the other struggles persist.

The price of being logged inIn six months, Ali has paid penalties worth Rs 1,150 on five separate occasions. His delivery ID has been blocked multiple times by Zomato. Each time, he has had to deposit additional money just to resume work. "Instead of saving, I keep paying the company. Penalties, deposits, daily

EV bike rent – everything is from my pocket," said Ali.

Like most gig workers, Ali is not considered an employee.He has no appointment letter, no salary slip, and no ID card. His proof of employment is limited to a uniform and a series of selfies the app demands at pickup points, delivery locations, and random checkpoints. Miss one, and deactivation follows. "How do I prove to anyone that I work for this company?" Only the app knows because they ask us to send a selfie after reaching the location," he said.

Waiting is also labour

Late-night deliveries bring a different kind of fear. Ali said that thieves often stop him, demanding money. He has narrowly escaped several times. "Standing on the road at night is also work. But nobody pays for waiting," he said.Customers cancel orders midway. Addresses change. Complaints are filed casually. Each incident pushes workers closer to penalties or suspension. There is no hearing, no explanation. The client, he said, is treated as infallible.

'Write To Me...': Chief Justice Surya Kant Dismisses Plea On 'Judicial Reforms'

New Delhi.(Agency)

Chief Justice of India Surya Kant on Monday dismissed a 'publicity-seeking' petition that sought the formation of a committee to oversee judicial reforms, including requiring every case to be settled within a 12-month period."We will not let anyone come here for 'judicial reforms'," the Chief Justice said, "If it is a matter of judicial reforms, I won't allow anyone to come to the court premises. First, put it in writing... whatever it is. Then I will see if it is possible or not. We are all here, we will do it."

The Chief Justice told the petitioner to "write a letter" to him with suggestions. "You want change in the country? Don't need to file such a petition... just write a letter and send it to me.""Don't file petitions just to speak in front of the cameramen standing outside."

On the plea for more courts to handle the vast number of cases, the Chief Justice said, "Aap keh rahe hai ek saal mein har court faisla kare? Aisi kitne courts chahiye apko?" ("You're saying every court should deliver a judgment within a year? How many such courts do you need?")"Court banva dijiye... court banva dijiye. kaha se banva dijiye?" ("Set up extra courts, set up extra courts. Where do we get these courts from?")Both issues had been erroneously intermingled, the court noted, also noting that the petitioner, if so inclined, may submit a letter on the administrative aspects to the Chief Justice with suggestions, if any, for the purpose of judicial reform.

"It goes without saying that any such suggestions are always welcome," the court said.

Top Renewable Energy-Producing State Rajasthan Needs More Coal Power By 2036

New Delhi.(Agency)

Rajasthan will need 4,400 megawatts of new coal-fired power capacity by 2036 to meet rising electricity demand despite India's top renewable energy–producing state adding more clean energy as it retires some ageing thermal plants, according to a government document.The Central Electricity Authority, a think tank of the federal power ministry, has more than doubled its earlier estimates of 1,900 MW coal-fired power for Rajasthan, according to a letter dated November 27 that was addressed to the state power utility and reviewed by Reuters. Rajasthan is preparing to retire its existing 1,350 MW old coal power projects, the document showed.

The Central Electricity Authority did not respond to a Reuters request for comment on the letter. India, which meets about a third of its power demand through thermal projects, has set a 2070 net-zero goal, which includes more than doubling national renewable capacity to 500 gigawatts.

Power consumption in India is expected to rise as its economy expands, requiring a 40% increase in coal-fired capacity to more than 307 gigawatts by 2035, as per government data.

With the upwards revision in the state's coal-based power needs, Rajasthan's power regulator has decided to review its November decision denying a permit for a new 3,200 MW coal power plant, according to a document posted on the regulator's website. The Rajasthan power utility had asked the regulator to review its decision, according to a separate document reviewed by Reuters.The company said additional coal capacity was needed because solar and wind energy was not available round the clock and battery storage systems were not yet ready. The state gets about 70% of its power from renewable sources.The state utility did not respond to Reuters request for comment.Several other states are also accelerating coal power procurement, citing strong demand and the need for reliable, baseload generation.

Delhi spends Rs 231 crore to tap hill rain in Yamuna, but not a drop flows in

New Delhi.(Agency)

Twenty-nine years ago, the governments of Delhi, Himachal Pradesh, and Uttarakhand signed a memorandum of understanding (MoU) for tapping monsoon flows in the Renukaji, Kishau, and Lakhwar dams to ease Delhi's water shortage. However, till today the plan remains on paper, with no work started to direct the flows to the Yamuna and its tributaries.The status of the project is confounding since the Delhi government has already paid Rs 230.73 crore for the three dams. Officials estimate the three reservoirs could meet the capital's drinking water needs for the next 25 years.

The Comptroller and Auditor General (CAG) has flagged the delay in a recent Delhi Jal Board (DJB) audit, noting despite their status as projects of national importance, construction has not yet begun owing to pending approvals from the Upper Yamuna River Board and the National Green Tribunal.

"In order to utilise the flow of the river during monsoon, an MoU was signed (November 1994) by the basin States to build two dams on Yamuna River, one at Renukaji in Himachal Pradesh and another at Kishau in Uttarakhand. Delhi Jal Board (DJB) made payment of Rs 230.73 crore for construction of Renukaji dam (Rs 214.84 crore), Kishau dam (Rs 8.10 crore) and another dam at Lakhwar (Rs 7.79 crore) to HP and Uttarakhand (UK) Governments (March 2022).

These projects were declared as projects of national importance. However, work on Renuka dam, Lakhwar and Kishau dams was under planning and approval stage with the Upper Yamuna River Commission (UYRC). The possibility of augmentation of raw water availability from Yamuna River in the near future is thus remote," the CAG noted.

Once completed, the Lakhwar dam can supply around 135 MGD to Delhi. The Renukaji and Kishau projects could add another 275 MGD and 372 MGD respectively, helping stabilise environmental flow in the river and reducing dependence on seasonal inflows.

HP, Uttarakhand dams can help capital create reserves for emergency usage

The Kishau multipurpose project, planned on the Tons river, a major Yamuna tributary, envisages a 236-metre-high dam with a live storage capacity of 1,324 million cubic metres. The project has faced prolonged delays due to inter-state disputes and financial challenges.

Local crimes, central control make Delhi unsafe

New Delhi.(Agency)

The Delhi Police recently carried out an exercise named Operation Gang Bust claiming they have arrested over 500 criminals. How does that help crime scenario in the national capital.

The crimes which occupy bold spaces like the murder of a Residents Welfare Association woman president in chief minister Rekha Gupta's constituency is typical example of policing having gone wrong at local levelDelhi's constitutional status as a Union Territory with an assembly has long produced a governance inconsistency. Citizens elect a government with expectations of safety, order and responsive administration, yet some critical levers of authority like policing remain outside the control of that government.

The result is a blurred accountability structure where power and responsibility are misaligned, and where failures in law and order often fall into an institutional no-man's land. Under the current arrangement, public order and police are vested with the Centre through the MHA, while the elected government is left to manage the consequences like public anger, political fallout and a crisis of confidence.

This structural disconnect is increasingly visible in Delhi's everyday crime scenario. To be clear, Delhi today

is not facing any extraordinary security emergency. There is no surge of terror activity or insurgent violence that demands exclusive, centralised micromanagement.

The city instead is grappling with crimes that are local, familiar and deeply personal like murders, extortion, neighbourhood disputes turning violent, and intimidation of community leaders. These are precisely the kinds of offences that require intimate local intelligence, sustained beat policing and swift accountability at the district level.

The murder in Shalimar Marg is illustrative of what has gone wrong. Such a crime is not just an individual tragedy; it is a warning signal of eroding community safety. It reflects failures in preventive policing, intelligence gathering and grievance redressal. Such failures that accumulate over time culminate in a crime most foul like murder. Unfortunately when such an incident occurs, the chain of accountability instead of tightening it scatters.For the Delhi Police, administrative control ultimately lies with the Centre. A grave local crime may not ring alarm bells in the distant corridors of North Block or Sewa Sadan with the same urgency it would in the Delhi Secretariat.

Delhi continues to witness severe AQI, cold wave conditions to persist

New Delhi.(Agency)

The national capital woke up to severe air quality again on Sunday, as levels worsened over the past two days, prompting the imposition of GRAP IV restrictions across the NCR on Saturday. Cold wave conditions and dense fog were also observed in the morning hours.The air quality index (AQI) stood at 440 in the 'severe' category as of 4 pm on Sunday, after recording 444 during the morning, data from the Central Pollution Control Board (CPCB) showed.

The city's AQI is expected to remain in the 'very poor' range from Monday to January 21 due to a lower

ventilation index of 6,000 units and an average wind speed of 10 kmph, not favorable for dispersing pollutants.

For Monday morning, the weather office predicted dense fog at isolated places across the capital, with maximum and minimum temperatures expected around 25°C and 8°C, respectively.

On Sunday, the capital recorded a maximum temperature of 22.7°C, 3.1 degrees above the seasonal average, with slightly cloudy conditions after dense morning fog, according to the IMD. The minimum temperature settled at 5.3°C, 2.3 degrees below normal. The Decision Support System assessment indicated that vehicular emissions contributed 12.47 per cent to overall pollution, while industrial emissions accounted for 7.8 per cent.

Three Delhi metro phase IV corridors get funding from govt

New Delhi.(Agency)

Aiming to expedite the capital's Metro network, the Delhi government has released its share of funds for the remaining three corridors of Phase IV of the Delhi Metro Rail Transit System (MRTS). Chief Minister Rekha Gupta on Sunday said these projects will significantly improve Metro connectivity across the capital and further strengthen Delhi's public transport system.

She said the new corridors will provide safe, convenient and time-efficient travel for commuters, reduce dependence on private vehicles and play a key role in controlling pollution. The three corridors are expected to be completed within four years.The three Phase-IV Metro corridors will have a combined length of 47.225 kilometres and are estimated to cost nearly Rs 14,630.80 crore. Of this, the government will contribute Rs 3,386.18 crore, officials said.

The first corridor will run from Lajpat Nagar to Saket G-Block and will be 8.385 kilometres long. It will have eight elevated Metro stations. The second corridor, from Inderlok to Indraprastha, will be 12.377 kilometres long and will include ten stations—one elevated and nine underground. These two corridors have been placed under a combined financial framework with a total project cost of `8,399.81 crore, of which the Delhi government's share will be `1,987.86 crore, the officials said.

The third and longest corridor will connect Rithala to Kundli, extending Metro connectivity to neighbouring Haryana. This 26.463-kilometre-long corridor will have 21 stations and is estimated to cost `6,230.99 crore. The Delhi government's share will be Rs 1,398.32 crore, while `545.77 crore will be spent in Haryana. Once operational, the Lajpat Nagar–Saket G-Block corridor will pass through Lajpat Nagar, Andrews Ganj, Greater Kailash-1, Chirag Delhi, Pushp Bhawan, Saket District Centre and Pushp Vihar.

The Inderlok–Indraprastha corridor will connect Inderlok, Dayabasti, Sarai Rohilla, Ajmal Khan Park, Jhandewalan, Nabi Karim, New Delhi Railway Station, Delhi Gate and Delhi Secretariat–IG Stadium.

The Rithala–Kundli corridor will serve areas including Rohini sectors, Barwala, Bawana Industrial Area, Narela, Sanoth and Kundli, significantly improving connectivity in north and northwest Delhi.

Officials said the tendering process is underway and basic work has already begun on some stretches. The construction of these corridors will reduce traffic congestion, save commuters' time and promote the use of public transport, helping Delhi move towards a cleaner and more sustainable future.

DMRC rebuilds sub station for Central Vista

The Delhi Metro Rail Corporation has completed the relocation and reconstruction of the Park Street Electric Receiving Sub Station as part of the Central Vista Project, ensuring uninterrupted power supply to key Metro corridors and support upcoming infrastructure in the city.

NEWS BOX

A Look At Prince Harry's Legal Battles With British Newspapers

United Kingdom. (Agency)

Prince Harry is to return to London this week for the trial into his claims that a UK newspaper group unlawfully gathered information, in the royal's last case in his long-running crusade against the media. The trial, expected to last up to nine weeks, is scheduled to start at London's High Court on Monday.

Prince Harry has had a turbulent relationship with the media and blames the press for the death of his mother Princess Diana, killed in a Paris car crash in 1997 as her car was pursued by paparazzi.

He and his wife Meghan stepped back from royal duties in 2020 and relocated to California, in part blaming relentless media attention.

Here is a breakdown of his legal cases:

Associated Newspapers

Harry along with musician Elton John, actor Elizabeth Hurley and others are suing the publisher of the Daily Mail and The Mail on Sunday newspapers alleging breaches of privacy.They accuse the newspapers of hiring private investigators, tapping phone calls and impersonating individuals to get medical information.Their lawyers said the events took place between 1993 and 2011, but some took place as late as 2018.The firm denies the claims and the trial is set to last nine weeks.Media law expert Mark Stephens told AFP the central question was whether the newspapers "truly stand apart from unlawful news gathering of that era or were they simply never dragged into the limelight" during earlier cases.In a separate case, Harry sued Associated Newspapers for libel in 2022 over a story about a legal battle he was having with the British government over his security arrangements.

The Mail on Sunday published an article suggesting Harry, also known as the Duke of Sussex, had tried to keep the legal challenge secret.The company argued the piece did not cause "serious" reputational harm and expressed an "honest opinion".

Harry lost the first part of the case and The Mail on Sunday later said he had withdrawn the claim before it went to trial.

News Group Newspapers

Harry settled his case against News Group Newspapers -- part of Rupert Murdoch's global media empire -- just before the trial was set to start in January last year.

CEO Of Iran's 2nd Largest Telecom Firm Fired For Failing To Block Internet

Iran. (Agency)

The chief executive of Irancell, Iran's second-largest mobile phone operator, was dismissed for failing to comply with the government's decision to shut down the internet, the Fars news agency reported Sunday.

In an unprecedented move, Iran cut off all communications on January 8 without warning, as calls intensified for anti-government protests, initially sparked by the economic crisis.Access to the internet has been virtually impossible in Iran since then, although restrictions began to ease Sunday for some foreign websites, such as Google.

"Alireza Rafiei was removed from the position of CEO of the company after about a year of activity," Fars reported."Irancell disobeyed the orders of the decision-making institutions in implementing the announced policies regarding the restriction of internet access in crisis situations," the agency said.

"The relevant institutions decided to dismiss the CEO of Irancell, citing 'failure to comply with the announced rules in crisis situations'," Fars added.

Iranian authorities have announced they are planning to restore internet access "gradually".

On Sunday morning in Tehran, AFP journalists were able to access the global internet, although most internet service providers remained blocked.The reasons for the limited connectivity were not immediately clear.Access to Google was restored on Sunday "via all mobile phone lines and internet service providers", according to state television.

Counter Of 'Islamic NATO' 'Mediterranean Quad' Could See India Join 3+1, Eyes On UAE

Dubai . (Agency)

United Arab Emirates (UAE) President Mohammed bin Zayed Al Nahyan will visit India today (January 19). The trip comes at a time of turbulence across the region. Concerns are rising over potential US attack on Iran, while Saudi Arabia and the UAE are at odds in Yemen. Pakistan is working with Turkey and Riyadh to form a military alliance along the lines of an Islamic NATO. It has raised strategic concerns for India.According to Eurasian Times, Saudi Arabia and Pakistan signed a defense pact last year. The agreement ensures that any attack on one is considered an attack on the other. Turkey could now join this pact.Meanwhile, India and the UAE are watching developments closely. Both countries may explore new alliances to counterbalance this emerging bloc.

A New 'QUAD' In The Making

Greece, Cyprus and Israel have formalised a trilateral military cooperation plan. The agreement includes joint exercises, unmanned systems, electronic warfare training and sharing expertise on regional stability. India has been invited to join this '3+1' summit and strategic forum. New Delhi already shares close ties with all three countries.The initiative follows a trilateral summit and includes detailed bilateral action plans. The plans points to a stronger security coalition to address shared threats, particularly as a strategic message toward Turkey. India joining Israel, Greece and Cyprus could create a powerful regional bloc.

Saudi, Pakistan And Turkey Alliance

The potential India-led Mediterranean Quad counters the growing influence of the Saudi-Pakistan-Turkey axis.

CBS investigative show '60 Minutes' airs Trump deportations report a month after being pulled

World. (Agency)

60 Minutes" on Sunday aired its story about Trump administration deportations that was abruptly pulled from the newsmagazine's lineup a month ago, a move that had triggered an internal battle about political pressure that spilled out into the open.Correspondent Sharyn Alfonsi made no reference to her dispute with CBS News editor-in-chief Bari Weiss in the story about deportees who had been sent to El Salvador's notoriously harsh CECOT prison. When the segment was struck from the Dec. 21 episode on Weiss' orders, Alfonsi told her "60 Minutes" colleagues that it "was not an editorial decision, it was a political one."Weiss had argued that the story did not sufficiently reflect the administration's viewpoint or advance reporting that had been done by other news organizations earlier.The story shown Sunday included no on-camera interviews with Trump administration officials. But it did include statements from the White House and Department of Homeland Security that were not part of what Alfonsi had used before her story was pulled. Some of statements, which were carried in full on the "60 Minutes" website, were dated prior to Dec. 21."Since November, '60 Minutes' has made several attempts to interview key Trump administration officials on camera about our story," Alfonsi said. "They declined our requests."Alfonsi did not immediately return a message from The Associated Press on Sunday. She said in her email that the administration's refusal to consent to on-camera interviews was a tactical maneuver designed to kill the story.CBS says it was always going to air the pieceCBS News, in a statement said, that its "leadership has always been committed to airing the "60 Minutes" CECOT piece as soon as it was ready. Tonight, viewers get to see it, along with other important stories, all of which speak to CBS News' independence and the power of our storytelling."Alfonsi's report was the second of three on Sunday's show, with the lead story being Cecilia Vega's report from Minneapolis about ICE enforcement efforts and the protests to its tactics. The initial decision to sideline Alfonsi's

CECOT story became a flashpoint for critics who said the appointment of Weiss, founder of the Free Press website who had no previous experience in television news, represented an attempt by the network's new corporate leadership to curry favor with Trump.While pulled from the broadcast in December, Alfonsi's original story mistakenly became available online. CBS News has fed a version of the newsmagazine to Global Television, a network that airs "60 Minutes" in Canada, which posted it on its website before the last-minute switch removing the piece.That enabled sharp-eyed viewers to see what Weiss had rejected, offering the opportunity to compare it to what "60 Minutes" eventually put on the air.The body of the story was unchanged. It included a brief clip of President Donald Trump saying the prison operators "don't play games," and one from White House press secretary Karoline Leavitt saying that "heinous monsters, rapists, murderers, sexual assaulters, predators who have no right to be in this country" were sent there.

Billionaires 4,000 times more likely to hold political office than ordinary people: Oxfam

DAVOS. (Agency)

As the rich and powerful from across the world start filling snow-clad lanes here, a new study said billionaires are 4,000 times more likely to hold any political office than ordinary people, and their wealth jumped three times faster in 2025 than the past-five-year average to a record high of USD 18.3 trillion.In Indian currency, it translates to more than Rs 1,660 lakh crore.

Hours before the 56th World Economic Forum Annual Meeting 2026 begins in this Swiss ski resort town, rights group Oxfam International released its own annual inequality report to highlight that the ever-deepening wealth divide was also sparking dangerous political inequality.The meeting is being attended by over 3,000 global leaders, including more than 60 heads of state or government, as part of an over 400-strong political leadership presence in this small town in the Alps.Oxfam International said the billionaire wealth jumped by over 16 per cent in 2025, while it has increased by 81 per cent since 2020."This comes as one in four people don't regularly have enough to eat, and nearly half the world's population live

in poverty," it added.The report, titled 'Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power', analysed how the super-rich were securing political power to shape the rules of our economies and societies for their own gain and the detriment of the rights and freedoms of people around the world.Oxfam said the surge in billionaire wealth coincided with the US Trump administration pursuing a pro-billionaire agenda, as it has slashed taxes for the super-rich, undermined global efforts to tax large corporations, reversed attempts to address monopoly power and contributed to the growth of AI-related stocks that have provided a boon to super-rich investors worldwide.Trump is among the top global leaders attending the WEF meeting.Oxfam said the Trump presidency has sent a clear warning sign to the rest of the world about the power of the ultra-rich and the rising oligarchy, which is undermining societies worldwide rather than being solely a US phenomenon.It said the collective wealth of billionaires last year surged by USD 2.5 trillion, almost equivalent to the total wealth held by the bottom half of humanity, or about 4.1 billion people.

Train collision in Spain kills 21, injures dozens

MADRID. (Agency)

Spain on Monday reeled from a collision between two high-speed trains in the southern region of Andalusia that killed 21 people and injured more than 70, with the prime minister lamenting a "night of deep pain".

The disaster struck on Sunday evening when a service travelling from Malaga to Madrid derailed near Adamuz, crossing onto the other track where it crashed into an oncoming train, which also derailed, Spain's Adif rail network operator posted on X.

A police spokesperson told AFP 21 people had died. Antonio Sanz, the top emergencies official in Andalusia, told a press conference that at least 73 people had been injured."The situation is likely to see the death toll increase," he said, adding that "a very complicated night awaits us".Transport Minister Oscar Puente told reporters that 30 people were rushed to hospital in serious condition, adding that all the injured had been evacuated to receive care.The disaster took place on a straight part of the track, which was completely renovated, Puente said, adding

that the first train to derail was "practically new", making the accident "extremely strange".

Rail operator Iryo said around 300 people were on board its Malaga-Madrid service.The hundreds of passengers left in the wreckage hampered the frantic work of emergency services."The problem is that the carriages are twisted, so the metal is twisted with the people inside," Francisco Carmona, head of firefighters in Cordoba, told public broadcaster RTVE.

"We have even had to remove a dead person to be able to reach someone alive. It is hard, tricky work," he added.

Some of the carriages had tumbled down an embankment of four metres, Sanz said at his press conference.

A horror movie'

A passenger on the second train, bound for the city of Huelva, who gave only her first name Montse, told Spanish public television the train, "with a jolt, came to a complete stop, and everything went dark".She described being thrown around in the last carriage and seeing luggage tumble on other passengers.

Helps Economically Disadvantaged': Oxfam Praises India's Quota In Politics

world. (Agency)

As it flagged billionaires usurping the political landscape globally, rights group Oxfam on Monday cited India's reservation system as a "compelling" example of progress on how ordinary people can be politically empowered.

In its annual inequality report released here on the first day of the World Economic Forum Annual Meeting, attended by rich and powerful from across the world, Oxfam International said billionaires are 4,000 times more likely to hold political office than ordinary citizens.Making a case for building 'the power of the many', Oxfam said ordinary people become powerful in a political system where political, institutional, and social conditions increase their capacity to influence decision-making despite structural inequality."This happens when institutional inclusiveness, political incentives for responsiveness, collective organisation, effective governance and ideological commitments align."Non-state actors such as CSOs, grassroots movements and trade unions are natural allies of states in building greater political

engagement from under-represented communities, and ensuring access for all to meaningful participation in policymaking," Oxfam said in the report, titled 'Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power'

.It said there are some compelling examples of progress on this crucial issue."In India, for example, political reservations (quotas) for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other marginalised groups create opportunities for economically disadvantaged and socially excluded communities to gain legislative representation and push redistributive policies," Oxfam said.India provides reservations for SCs and STs, as well as a few other sections, in legislatures, as per their population, while it has recently also announced 33 per cent for women.

In addition to these categories, there are reservations for other weaker and marginalised groups as well in education and government jobs.Oxfam also cited the example of Brazil's Participatory Budgeting that emerged in the 1990s and saw significant expansion during the 2000s."Its most prominent example was the city of Porto Alegre, whose experience became an international reference in participatory democracy by allowing citizens to directly decide on portions of the municipal public budget," Oxfam said.

China's economy grows 5% in 2025, buoyed by strong exports despite Trump's tariffs

HONG KONG. (Agency)

China's economy expanded at a 5% annual pace in 2025, buoyed by strong exports despite U.S. President Donald Trump's tariffs.However, growth slowed to a 4.5% rate in the last quarter of the year, the government said Monday. That was the slowest quarterly growth since late 2022 when China was beginning to loosen stringent COVID-19 pandemic restrictions. The economy, the world's second largest, grew at a 4.8% annual pace in the previous quarter.China's leaders have been trying to spur faster growth after a slump in the property market and disruptions from the pandemic rippled through the economy.

As expected, annual growth last year was in line with the government's official target for an expansion of "around 5%."Strong exports helped to compensate for weak consumer spending and business investment, contributing to a record trade surplus of $1.2 trillion."The key question is how long this engine of growth can remain the primary driver," Lynn Song, chief economist for Greater China at Dutch bank ING wrote in a recent note.Chinese exports to the U.S. suffered after President Donald Trump returned to office early last year and began raising tariffs. But that decline was offset by shipments to the rest of the world. Soaring imports of Chinese goods are leading some other governments to take action to protect local industries, in some cases raising import duties."Should more economies also start ramping up tariffs on China, as Mexico has done and the E.U. has threatened to do, eventually, a tighter squeeze will be seen," said Song.

China's leaders have repeatedly highlighted boosting domestic demand as a policy focus, but their effects have so far been limited. A trade-in program for drivers to replace older cars with more energy-efficient models, for example, has been losing steam in recent

months."Stabilization, not necessarily recovery, of the domestic property market is key to revive public confidence and, hence household consumption and private investment growth," said Chi Lo, senior market strategist for Asia Pacific at BNP Paribas Asset Management.China has also provided trade-in subsidies for home appliances such as refrigerators, washing machines and TVs. While major consumer stimulus policies in 2025 -- including such subsidies -- are set to continue in 2026, they may be scaled back, Weiheng Chen, global investment strategist at J.P. Morgan Private Bank, said in a recent note.

Investments in artificial intelligence and other advanced technologies remain a key priority for China's ruling Communist Party as it moves to boost self-reliance and rival the U.S. Meanwhile, many ordinary Chinese and small businesses are struggling with tough times and troubling uncertainty over jobs and incomes.Liu Fengyun, a 53-year-old noodle restaurant owner in a small county in southwestern China's Guizhou province, said business has become very difficult these days. Some of her customers told her that "money is hard to earn now" and "making breakfast at home is cheaper.""People all say, 'The overall environment is not good right now — what more can you expect? People don't have money anymore. Nothing is easy to do now,'" Liu said.Some economists and analysts believe China's actual economic growth in 2025 was slower than official data suggest.

NEWS BOX

Usain Bolt hints at return from retirement to play cricket at LA 2028 Olympics

New Delhi. (Agency)

Jamaican sprinting legend Usain Bolt has expressed his desire to return to the Olympic Games in Los Angeles in 2028, this time with ambitions of participating in cricket. The sport is set to make its much-anticipated return to the Olympics after a 128-year absence, taking centre stage at the LA28 Games, scheduled to run from 12 to 29 July 2028.As cricket prepares for its comeback at the quadrennial event, Bolt has revealed his enthusiasm to represent his country with a bat and ball. Growing up in the cricket-mad Caribbean, Bolt was originally an aspiring fast bowler before he went on to become the most recognisable sprinter the world has ever seen.Cricket was, in fact, Bolt's first sporting love before he was encouraged to try his hand at track and field by his cricket coach during his high school years. That decision ultimately changed the course of sporting

history, but Bolt has never hidden his affection for the game.Speaking to Esquire magazine, Bolt joked that he would be more than willing to answer the call should Jamaican cricket authorities reach out to him."I am happily retired from professional sport. I haven't played cricket in a long time, but if they call, I will be ready! [Laughs]," Bolt told Esquire.Bolt is widely regarded as the greatest sprinter of all time, boasting an extraordinary record of eight Olympic gold medals and 11 World Championship gold medals. He retired from athletics in 2017 as the most decorated sprinter in history, having swept the 100 metres and 200 metres titles at three consecutive Olympic Games — Beijing 2008, London 2012 and Rio 2016.Bolt was also named the brand ambassador of the T20 World Cup 2024, which was held in the USA and West Indies. He also played friendly cricket match in India back in 2014 alongside Yuvraj Singh and Harbhajan Singh. Bolt continues to hold the world records in both the 100 metres (9.58 seconds) and the 200 metres (19.19 seconds), which he set at the 2009 World Championships in Berlin — marks that remain untouched more than a decade later.

Ironwoman in a man's world: India's Renee Noronha aims to rewrite history

In an exclusive chat with India Today, India's youngest female Ironman athlete, Renee Noronha, opens up about her world record aspirations and making a positive change for women in endurance sports.

New Delhi. (Agency)

When you talk to Renee Noronha you almost feel a sense of calmness around her. The athlete, who recently turned 20 years old, speaks with such poise that you tend to easily forget that she is the youngest Indian woman to complete an Ironman challenge when she was 18 years and 49 days.When talking to India Today exclusively, Renee said that she is a family person off the track and loves spending time with her dog, Sky. A 'Swiftie' at heart, she says attending a Taylor Swift concert was a dream come true moment for her.When I'm not training or I'm not racing, I love spending time with my family. And I enjoy taking my dog, Sky, for walks. I love playing with him, and I also like listening to music. I listen to a lot of Taylor Swift. And I also attended a concert, and that was like one big moment. It was like a dream come true, and listening to her perform, it was amazing," said Renee.But don't be fooled by her smile and calmness. When she is on the track, Renee never fails to deliver and is always looking to better herself and beat her own timings.Having completed Ironman New Zealand in 2024 and Hamburg last year, Renee's goal is not just to smash a world record but a make a change and inspire more women to enter into the world of triathlons.

Gymnastics to Triathlons

For Renee, the start wasn't actually with running, swimming or even cycling. It was actually with gymnastics. The 20-year-old said she was a livewire as a kid and her parents decided it was best to channel her energy in gymnastics."I was always a very

active kid. I was constantly doing cartwheels and running around the house. So my parents decided to put me into gymnastics class, and I did that for 10 years," said Renee.But when she was 16, the female Ironman athlete felt she could do more and actually push her limits."At the age of 16, I felt I could do more. I wanted to try something different, and that's when I started running. I loved running, and I always felt I could do more, and that's when I started swimming and cycling, and I met my coach, and decided that I want to do an Ironman. And then in 2024, I did my first Ironman," said Renee.While she made the transition sound so easy, it was far from it. The 20-year-old admitted that before she started her swim in Ironman New Zealand, there was a bit of nerves as the weather conditions weren't ideal."So, before starting the swim. I was a little scared because it was my first time participating in an Ironman challenge. But the swim, it went well, and the biking as well, despite the strong headwinds and the harsh weather conditions. Nothing can really prepare you for race day, cause you, you can't predict what the weather will be like.""A few days before the race, it was nice and sunny, and then on the day of the race, there was like an actual hailstorm, and it was raining. But, during those moments, you just need to trust your training and just keep moving so you keep yourself motivated throughout the whole race," said Renee.

ICC tells Bangladesh to play T20 World Cup in India or be replaced: Sources

NEW DELHI. (Agency)

"The International Cricket Council has warned Bangladesh Cricket Board to either play in India or risk getting replaced by a lower-ranked team in the T20 World Cup. Sources have told India Today that ICC has given Bangladesh time until January 21 to take a call, beyond which the global cricket body will look to replace Bangladesh.

The ultimatum from the ICC comes a day after Bangladesh proposed a radical idea, urging the global body to switch their group in the T20 World Cup so that they can avoid playing in India. The BCB made this stance public, following their meeting with the ICC delegation, which travelled to Bangladesh to discuss the ongoing T20 World Cup crisis.At the heart of the dispute is Bangladesh's refusal – so far – to play its scheduled group-stage matches in India, even though the 2026 Men's T20 World Cup is officially co-hosted by India and Sri Lanka from February 7 to March 8, 2026.Bangladesh's fixtures, as released by the ICC in November, place them in a

group whose matches are slated for Indian venues – Kolkata (Eden Gardens) and Mumbai (Wankhede Stadium).The BCB has publicly framed its position as a security-driven decision, insisting it does not want the team travelling to India for the tournament.The ICC, however, has signalled it is not inclined to rewrite the tournament plan at short notice. Sources said ICC sees no grounds to relocate those matches. The stalemate has intensified because the tournament is only weeks away, forcing the ICC into direct talks with the BCB to avoid a precedent-setting crisis.

Tata Steel Masters: Praggnanandhaa goes down again, Gukesh held by Foreest

NEW DELHI. (Agency)

Defending champion R Praggnanandhaa lost his second game in as many days, going down to Nodirbek Abdusattorov of Uzbekistan, even as D Gukesh was held to a draw by the Netherlands' Jorden van Foreest in the Tata Steel Masters Chess here.Having been at the top of his game for a major part of 2025, Praggnanandhaa seems to be running low on steam as a drawn endgame turned into a painful loss against the Uzbek on Sunday.With no points to show after the first two games, Praggnanandhaa is at the bottom of the table and will have to make a strong comeback in the remaining 11 rounds in order to pose a challenge.Meanwhile world champion Gukesh was held to a draw by van Foreest in another hard-fought game. Gukesh took his tally to one point following his second draw.

After defeating Praggnanandhaa in the opener,

Arjun Erigaisi tried to make a foray against Thai Dai Van Nguyen of Czech Republic but eventually did not succeed in breaking the fortress.The top seeded Indian however remained in joint lead on 1.5 points in the company of Hans Moke Niemann of the United States and Abdusattorov.

The fourth Indian in the fray Aravindh Chithambaram played out a draw with Yagiz Kaan Erdogmus of Turkey to also take his tally to one point out of a possible two.With three players in front, as many as nine are in closed pursuit a half point behind with local star Anish Giri on 13th spot on a half point just ahead of Praggnanandhaa.It was a Queen's Gmabit declined by Praggnanandhaa and it did not seem he had any trouble equalising with the black pieces. Nodirbek waited for the position to open up and went a pawn ahead in the rook and pawns endgame after the Indian erred on his 31st move.However, there were still huge technicalities and the experts believed that the endgame should have been a draw.Praggnanandhaa could not really find the way to equalise and had to surrender on his 60th turn. Arjun also employed the Queen's gambit and suffered a little in the early stages of the middle game.

Walkout, 94th-minute winner: Senegal snatch AFCON title from Morocco in chaotic Final

NEW DELHI. (Agency)

There was drama and chaos in the African Cup Of Nations final on Sunday, January 18 as Senegal walked off the field in protest at a penalty being awarded against them before returning to the field and beating hosts Morocco in extra-time to claim the title.

Midfielder Papa Gueye netted the winner in the 94th minute after Real Madrid midfielder Brahim Diaz squandered the chance to win the title for Morocco by missing a last-gasp penalty after a delay in the game was caused by the Senegal team walking off the field.HOW THE DRAMA UNFOLDED IN AFCON FINAL

The chaos erupted in the 92nd minute when Senegal thought they had scored, only for the referee to disallow the goal for a foul inside the Morocco box.But there was more drama to follow when Diaz was deemed to

have pulled down to the ground by El Hadji Malick Diouf and Morocco was awarded a penalty.Officials and players were seen going at each other as referee Jean-Jacques Ndala consulted with VAR and gave the spotkick. This caused Senegal coach Pape Bouna Thiaw to order his players to walk off the pitch.The Senegal players made it back to the field only after being convinced by captain Sadio Mane and the game continued almost after 20 minutes.

But the advantage was with Morocco as the penalty was still standing and Diaz stepped up. However, the madness of the night was set to continue as the midfielder attempted a panenka kick and Edouard Mendy easily saved his effort.The game looked destined to go to penalties but Gueye had other ideas to complete the fairytale for Senegal. In the 94th minute, he stepped up with a solo effort and then a thunderous shot to send the fans into ecstasy.

Like Nadal on clay: Meet An Se Young, the badminton star impossible to beat

New Delhi. (Agency)

Ratchanok Intanon was asked following the women's singles semi-final at the India Open on Saturday. She paused. A slow, knowing smile spread across her face – a look that spoke louder than any tactical breakdown.One of the world's most versatile shot-makers and a former World No. 1, Ratchanok found herself unable to answer the most haunting question on the badminton tour. Her 11-21, 7-21 dismantling was her 13th defeat in 14 meetings against the reigning Olympic champion, An Se-young.While the 30-year-old Ratchanok-a legend in her own right-conceded she needs more speed to survive, even the youth and power of World No. 2 Wang Zhi-yi offered no resistance. In Sunday's final, the Chinese star was blown away in a mere 43 minutes, falling 13-21, 11-21. It extended An's dominance over her primary rival to 10-0 since the start of 2025.She is stable at the net and she is fast. She is strong, she is comprehensively good in every aspect," Wang admitted. "She has been one of the strongest opponents for me."

A CODE NOBODY HAS CRACKED

Over the last 14 months, the badminton world has been searching for a glitch in the South Korean's matrix. None exists. The 23-year-old, instantly recognisable by her trademark headband, is dubbed 'Rambo.' She may lack the rugged physique of the cinematic icon, but once she crosses the service line, she is a one-woman demolition crew.The numbers are staggering. In 2025, An Se-young won 73 matches and lost only four. Her 11 titles equalled Kento Momota's all-time record for a single season, while her 94.8% win rate vaulted her into the realm of the sport's immortals. She has carried that momentum into 2026, sweeping the Malaysia Open and defending her New Delhi crown on January 18-her sixth consecutive title.

In the stands on Sunday, the atmosphere was telling. Among the Korean contingent, there were no frayed nerves or desperate cheers-only a quiet, clinical certainty. They watched not with the anxiety of fans, but with the detachment of observers witnessing the inevitable.

LEAGUE OF ONE

In elite sport, top-tier clashes usually imply parity. When Carlos Alcaraz and Jannik Sinner meet on a tennis court, the world prepares for a marathon. Yet, a final between the World No. 1 and No. 2 in badminton now feels like a mismatch. An Se-young isn't just leading the pack; she is light-years ahead.She has perfected a terrifying alchemy of defence, offence, and court coverage. Her footwork allows her to retrieve the "impossible" while remaining eerily composed.

Rohit-Kohli in Tests, Jadeja in ODIs: Career-killers New Zealand strike again

INDORE. (Agency)

This loss will sting," former India cricketer Aakash Chopra said after India surrendered their three-match ODI series against New Zealand on Sunday, January 18. Playing at the Holkar Stadium in Indore, Shubman Gill's India failed to chase down 338, losing the decider by 41 runs and, with it, the series 2–1, against what was effectively a B-string New Zealand side.

The scoreline hurt. But perhaps, the context hurt more.This is the second time in the last year and a half that New Zealand have handed India a sharp reality check. In 2024, Tom Latham's side walked into India's backyard and whitewashed them 3–0 in Tests, scripting a first in New Zealand cricket history. That defeat had consequences. It fast-tracked a transition that Indian cricket had been delaying — Rohit Sharma, Virat Kohli and Ravichandran Ashwin exited the Test setup soon after.That series loss forced India to confront uncomfortable truths in red-ball cricket. Fourteen months later, New Zealand have done it again, this time in the ODI format. Michael Bracewell's side may not have arrived with their biggest names, but they left with the same effect: by raising some uncomfortable questions.If history is anything to go by, a home series defeat in Indian cricket rarely stays confined to the boundary ropes. Murmurs begin quietly before turning into agenda items in selection meetings and review panels. This loss will be no different. Perhaps even more so, because India do not play another ODI for the next five months — time enough for introspection to harden into decisions.With the road to the 2027 ODI World Cup beginning to take shape, the spotlight will inevitably turn to the senior players first. Transitions, in Indian cricket, are rarely democratic.But who exactly will pay the price?

Career Killers New Zealand Strike Again

Virat Kohli appears secure for now, having reinvented his batting tempo over the last

three months and adapting to the demands of modern ODI cricket. Rohit Sharma, though, may not escape scrutiny as easily. Against an inexperienced New Zealand attack, he got starts but failed to convert them into the kind of defining innings his reputation demands. There will be those who argue that this was a one-off — after all, Rohit had productive series against South Africa and Australia in 2025 — but doubt has a way of lingering.

Only three players in India's ODI squad are above the age of 36. With Kohli largely insulated and Rohit still backed by recent performances, attention is likely to settle on Ravindra Jadeja."Ravindra Jadeja is a point of concern. It is simply not happening for him. This loss will sting," Chopra said on his YouTube channel.The numbers back up that discomfort. Jadeja went wicketless across the entire series — the first time since 2017 that he has failed to take a wicket in three consecutive ODIs. With the bat, the returns were no better. On Sunday, in what could only be described as a brain-fade moment, Jadeja threw his wicket away when Kohli needed him to simply hold one end. Harshit Rana, a lower-order batter by role, ended the series with a stronger batting impression.

THE PHOTON NEWS

Nora Fatehi

Reacts To Alleged Bhushan Kumar Affair Amid Dating Rumours With Achraf Hakimi

Speculation surrounding actor-dancer Nora Fatehi and T-Series head Bhushan Kumar has once again found its way back into online discourse. The rumours, which date back to 2022, had alleged that Bhushan was involved in an affair with Nora despite being married to filmmaker Divya Khosla Kumar.At the time, film critic Umair Sandhu had claimed that the alleged relationship had been ongoing for nearly two years and that Divya was aware of it. Parallel rumours of a separation between Bhushan and Divya also surfaced but were later dismissed by the couple.

Old Reddit Comment Triggers Fresh Buzz

The controversy has been reignited after a TikTok influencer resurfaced a three-year-old Reddit thread discussing the alleged affair. The thread went viral once again when users noticed a comment from Nora herself, in which she reacted with a brief "Wow" followed by a laughing emoji.

A screenshot of the comment was shared on Reddit with the caption referencing Nora's reaction to a TikTok discussing the alleged relationship. The post quickly drew mixed reactions. While some users found the response amusing, others questioned why the actor would react to an old rumour, with one comment reading, "Why even comment? Now it'll just bring more attention."

Who Is Nora Fatehi Reportedly Dating Now?

Amid the renewed speculation, Nora has also found herself linked to Moroccan football star Achraf Hakimi. Dating rumours gained traction after Hakimi liked one of Nora's social media posts, followed by the actor being spotted in Morocco.Fuel was added to the speculation when Nora shared pictures from the country during the Africa Cup of Nations, posing in a red jacket, white crop top, and jeans. While neither has confirmed the relationship, online chatter has continued to grow.

About Achraf Hakimi

Achraf Hakimi is a professional footballer who plays for Paris Saint-Germain as well as the Moroccan national team. Known for his explosive pace and attacking strength as a right-back, Hakimi has previously represented clubs like Real Madrid and Inter Milan, winning several domestic and international titles.

Farah Khan Reacts In Shock As Cook Dilip Says He Uses Her BMW For Travel

Farah Khan's YouTube vlogs are known for food, fun and unfiltered moments, but it's her cook Dilip who often ends up stealing the show. The filmmaker's latest vlog delivered another laugh-out-loud moment when Dilip casually revealed that he travels around using Farah's BMW, leaving her both shocked and amused.In the recent episode, Farah visited the Mumbai home of Bigg Boss 19 contestant Pranit More along with Dilip. While the trio cooked and chatted about Pranit's journey into stand-up comedy, the conversation took an unexpected turn when Pranit's father brought up a luxury car spotted in one of Farah's earlier videos.

Reacting to the question, Farah laughed it off and clarified that Dilip still commutes on a two-wheeler. She then turned to Dilip to confirm whether he had actually bought a car of his own. That's when Dilip dropped the bombshell, saying, "Aapka BMW wala hain na (Your BMW is there)!"

The room erupted in laughter as Pranit joked that Dilip must be telling everyone back in his village that the BMW belongs to him. The surprise didn't end there. Pranit's father added that he had once seen Dilip travelling in the car with a driver, prompting a stunned Farah to react, "Driver bhi tha? Ubed and ye dono kaha ghum raha tha Lonavala mein (With the driver? Ubed and him are going around with my car but where)?"

Dilip could only giggle at the remark, choosing not to explain further.Dilip has become a recurring star in Farah's vlogs over time. In an earlier video, he spoke about starting his career in Delhi with a salary of just ₹300, before landing a job at Farah's home for ₹20,000. Farah later revealed that his earnings have grown substantially and that he also receives additional income or a share from their YouTube content.

The filmmaker has also expanded her content with Dilip beyond the kitchen. She recently launched a travel vlog series featuring him, which included his first-ever international trip to the Maldives. His growing popularity has even led to brand endorsements, with Dilip appearing in advertisements alongside Shah Rukh Khan and Kiara Advani for Myntra, as well as campaigns for Flipkart and other brands.

Akshay Kumar And Twinkle Khanna Go Paragliding On Their 25th Wedding Anniversary

Akshay Kumar and Twinkle Khanna are celebrating their 25th wedding anniversary. Earlier today, the 'Jolly LLB 3' actor shared a humorous yet sweet post to wish his wife on this special occasion. Now, Twinkle Khanna has shared a sneak-peek into how they celebrated their wedding anniversary. The couple spent an adventurous day and went paragliding together! In her caption, Twinkle summed up their relationship and joked that they 'literally' encourage each other to fly.

Akshay Kumar And Twinkle Khanna's 25th Wedding Anniversary

On Saturday evening, Twinkle Khanna shared a video on Instagram that shows her and Akshay Kumar enjoying a paragliding adventure. In the clip, Akshay can be heard asking Twinkle if she is sure about jumping as she gets strapped into the harness. Even though she seems nervous initially, she replies, "Yes. All because of you." She then takes the leap and soars through the air while Akshay happily records the moment. The video then shows Akshay getting ready for his turn, with Twinkle asking if he's nervous before he takes off.

In her caption, Twinkle Khanna wrote, "The best part of our marriage? We always encourage each other to fly. Sometimes literally, like today! Here's to 25 years of love, support and jumping off mountains @akshaykumar." Soon after she shared the post, Bobby Deol, Malaika Arora, Namrata Shirodkar and many others wished them a happy wedding anniversary.

Akshay Kumar's Post For Twinkle Khanna

Meanwhile, in his post, Akshay Kumar recalled his mother-in-law Dimple Kapadia's helpful warning for him as he was getting married to Twinkle Khanna.

He revealed Dimple told him to get ready to laugh in the most weird situations. "When we got married this day in 2001, her mother had said 'Beta, get ready to burst out laughing in the most weird situations because she'll do exactly that'.25 years and I know ki meri mother-in-law kabhi jhooth nahi bolti hai… her daughter refuses to even walk straight… she prefers to dance through life instead (sic)," he wrote.

Sara Arjun

Reveals Vijay Deverakonda Is Her Favourite Telugu Actor

Sara Arjun rose to stardom with her performance in Ranveer Singh's Dhurandhar. The actress is currently basking in the success as the film continues to run strong at the box office. However, amid this, she is also busy with the shoot of other films too. Recently, her film Euphoria trailer was released, and Sara Arjun revealed the one star who truly inspires her — Vijay Deverakonda.At the recent trailer launch of Euphoria, Sara Arjun was asked which actor she admires the most and her reply grabbed attention. She mentioned that Vijay Deverakonda is her most admired and favourite star.

Sara Arjun's work

She explained that while she wanted to stick to her original plan, two films — Euphoria and Magic — stood out immediately. According to her, "These were stories that I felt needed to be told in our society, stories that could spark conversations and reflection. So beyond the hunger of an actor to perform, I felt, on a human level, a deep urge to be part of bringing these narratives to the screen." Sara added that the themes explored in both films felt especially important for young people today. "For today's youth, which I am a part of, I feel these themes are not just relevant but essential. That is why we chose to do these films first and then continue with my plan of pursuing further studies in acting abroad."But the timeline moved quickly. While appearing for her Class 12 board exams, Sara signed Magic. Soon after completing school, Euphoria followed. Both projects, she noted, revolve around emotionally demanding teenage characters and helped her evolve as a performer.During the shoot of Euphoria, she balanced packed schedules across cities. "While shooting for 'Euphoria', I flew overnight after pack-up to meet Aditya Dhar Sir the next morning and then returned the same day to resume shooting. It ended up being a really fun day."

Vijay Deverakonda's work

Vijay Deverakonda sparked fresh excitement among fans as he officially announced his next film, Rowdy Janardhana. It features Keerthy Suresh as the female lead. Sharing the first promo on Instagram, the actor revealed the film's release timeline with the caption, "The Biography of a Wounded man. in 1 year. #RowdyJanardhana December 2026." The promo is packed with gritty action and violent imagery, hinting at a dark. raw narrative.